हिन्दी दैनिक

सत्ता संकेत

शनिवार, 14 सितंबर 2024, लखनऊ | sattasanket@gmail.com | R.N.I. No.: UPHIN/2016/69492 | वर्ष 09, अंक 102 04 पेज, मूल्य ₹1.00

डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के स्थापना दिवस पर बोले, योगी

5 वर्ष में खत्म होगी डॉक्टरों की कमी

लखनऊ, एजेंसी।

अब जड़ से खत्म हुआ इंसेफेलाइटिस: सीएम योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि डॉ0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान विगत 14 वर्षों की अल्प अवधि में एक चिकित्सालय से इंस्टीट्यूट बनकर उत्तर प्रदेश एवं भारत के बेहतरीन चिकित्सा व स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में उभरा है। यह संस्थान की एक उपलब्धि है। यही जीवन की विकास यात्रा है, जिसको हमारी ऋषि परम्परा ने संस्कृति कहा है। बीज का वृक्ष बन जाना ही संस्कृति है।

मुख्यमंत्री जी आज यहां डॉ0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के चतुर्थ वार्षिक स्थापना दिवस समारोह का मुख्य अतिथि के तौर पर शुभारम्भ करने के पश्चात अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने संस्थान के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण तथा संस्थान की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट का विमोचन किया। उन्होंने वर्ष 2023-24 ■ शेष पेज 03 पर

यूपी में बारिश का कहर जारी, सात मरे

लखनऊ, एजेंसी।

उत्तर प्रदेश में पिछले दो दिनो से हो रही बारिश की तीव्रता में शुक्रवार को मामूली कमी आयी। बारिश के कारण नदियों के उफनाने से कई इलाकों में बाढ़ का खतरा गहरा गया है वहीं दर्जनों गांव का संपर्क मुख्य मार्ग से कट गया है। पिछले 24 घंटों में वर्षा जनित हादसों में कम से कम सात लोगों की मृत्यु हो गयी है।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में अतिवृष्टि एवं आकाशीय विद्युत से हुई जनहानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है और दिवंगत व्यक्तियों के परिजनों को चार चार लाख रुपए की अनुमन्य राहत राशि तत्काल वितरित किए जाने के निर्देश दिये हैं। उन्होने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्य के लिये एनडीआरएफ, एसडीआरएफ तथा पीएसी की टीमें तैनात करने के निर्देश दिये हैं।

उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को मिला जीत का प्रमाण पत्र

पत्रकार हितों के लिए सरकार प्रतिबद्धः संजय प्रसाद

लखनऊ, संवाददाता।

उत्तर प्रदेश राज्य मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति के नव निर्वाचित पदाधिकारियों और सदस्यों को शुक्रवार को जीत का प्रमाण पत्र दिया गया। लोक भवन में आयोजित प्रमाण पत्र वितरण समारोह में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद,निदेशक शिशिर व मुख्य मंत्री के मीडिया सलाहकार रहीस सिंह शामिल हुए।

प्रमाण पत्र वितरण समारोह को संबोधित करते हुए प्रमुख सचिव सूचना संजय प्रसाद ने सभी निर्वाचित पदाधिकारी और सदस्यों को बधाई दी।उन्होंने लंबे समय से लंबित

समारोह में पत्रकार कल्याण कोष, स्वास्थ्य, पेंशन और लघु व मध्यम समाचार पत्रों के आर्थिक संकट की मांग उठाई गई

पत्रकारों की विभिन्न समस्यों के निस्तारण का आश्वासन दिया।

प्रमुख सचिव सूचना ने कहा की समिति की जो भी अन्य मांगे है उसे सूचीबद्ध कर लिखित रूप से अवगत कराएं। पत्रकारों हितों के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।चुनाव समिति के शरत प्रधान, वीरेन्द्र सक्सेना व सुरेश बहादुर सिंह ने भी सभी निर्वाचित पदाधिकारियों व ■ शेष पेज 03 पर

खास खबर

अब पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम होगा

नयी दिल्ली। गुलामी के प्रतीकों से मुक्ति दिलाने की सरकार की मुहिम के तहत गृह मंत्रालय ने पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम करने का निर्णय लिया है। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा , देश को गुलामी के सभी प्रतीकों से मुक्ति दिलाने के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के संकल्प से प्रेरित होकर आज गृह मंत्रालय ने पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम करने का निर्णय लिया है। श्री विजयपुरम नाम हमारे स्वाधीनता के संघर्ष और इसमें अंडमान और निकोबार के योगदान को दर्शाता है।उन्होंने कहा कि इस द्वीप का हमारे देश की स्वाधीनता और इतिहास में अद्वितीय स्थान रहा है।

पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलने के निर्णय का योगी ने किया स्वागत

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल कर श्री विजयपुरम करने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के फैसले की सराहना की है और उनके प्रति आभार व्यक्त किया है।श्री योगी ने एक्स पर पोस्ट किया आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में आज पोर्ट ब्लेयर का नाम 'श्री विजयपुरम' करने का निर्णय 140 करोड़ भारत वासियों की भावना के अनुरूप है।उन्होंने कहा देश को गुलामी के सभी प्रतीकों से मुक्ति दिलाने के प्रधानमंत्री जी के संकल्प को आगे बढ़ाता यह ऐतिहासिक निर्णय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सभी बलिदानियों और सेनानियों को पूरे देश की ओर से समेकित श्रद्धांजलि है।मुख्यमंत्री ने कहा स्वाधीनता संघर्ष में अंडमान और निकोबार के योगदान को दशार्ता श्री विजयपुरम नाम हमें अपने देश के गौरवशाली अतीत और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, 'स्वातंत्र्यवीर' वीर सावरकर जैसे माँ भारती के अनेक अमर सपूतों के संघर्षों और बलिदानों की पावन स्मृतियों से जोड़ता है।

किश्तवाड़ में मुठभेड़: जवान शहीद, 2 घायल

जम्मू। जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के छतरू इलाके में शुक्रवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में दो जवान शहीद हो गए और दो अन्य घायल हो गए।सेना ने कहा कि विशेष सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने छतरू क्षेत्र के नैदघाम इलाके में घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया। इस दौरान सुरक्षा बलों के जवान जब एक निश्चित इलाके की ओर बढ़ रहे थे, तो वहां छूपे हुए आतंकवादियों ने उन पर गोलियां चलायी। इसके बाद सुरक्षा बलों के जवानों ने जवाबी कार्रवाई में गोलियां चलायीं। सेना ने कहा, चटरू इलाके के नैदघाम गांव के ऊपरी इलाकों में पिंगनल दुगड्डा वन क्षेत्र में सुरक्षा बलों की तलाशी टीमों और छिपे हुए आतंकवादियों के बीच गोलीबारी हुई।

मुख्यमंत्री योगी जी डॉ0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के चतुर्थ वार्षिक स्थापना दिवस समारोह में संस्थान की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट का विमोचन करते हुए।

अबकी बार 10 पार!

यूपी विधानसभा उपचुनावों में रंग ला सकती है भाजपा की मेहनत

लखनऊ, एजेंसी।

उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके दिग्गज मंत्री सभी दर्सों सीटों पर चुनाव प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। बीजेपी की मेहनत कितना रंग लायेगी यह तो भविष्य के गर्भ में छिपा है, परंतु बीजेपी की कार्यकर्ता काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं।

यही वजह है पार्टी के भीतर टिकट को लेकर दावेदारों की फौज खड़ी हो गई है।बीजेपी प्रत्याशियों की विपक्ष से लड़ाई तो बाद में होगी, इससे पहले टिकट को लेकर ही पार्टी के भीतर ही जंग शुरू हो गई है। टिकट को लेकर छिड़ी जंग का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि दावेदार आपस में ही एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं। अम्बेडकर नगर की कटेहरी सीट पर टिकट को लेकर स्थानीय भाजपा इकाई दो फाड़ हो चुकी है। दोनों खेमा एक दूसरे के खिलाफ शिकायतों का पिटारा भाजपा नेतृत्व के पास भेज रहा है।

प्रदेश संगठन ने पिछले दिनों शिकायतकताओं को प्रदेश मुख्यालय में बुलाकर उन्हें समझाया भी था। वहीं, अंबेडकर के दौरे पर गए संगठन के पदाधिकारियों ने भी उन्हें शांत रहने की नसीहत दी थी। इसके बावजूद उनके बीच रार जारी है।सूत्रों की मानें तो पार्टी से बाहर के कुछ कद्दावर हस्तियां भी टिकट की उम्मीद लगाये बैठी हैं। कटेहरी,

विधानसभा उपचुनाव में जीत के लिए बनाई रणनीति

गाजियाबाद, फूलपुर और मझवां सीट पर कुछ बाहरी लोगों को टिकट दिलाने को लेकर भाजपा के दो बड़े नेता भी लखनऊ से दिल्ली तक लाबिंग कर रहे हैं। मीरापुर सीट पर पूर्व सांसद मलूक नागर और पूर्व विधायक राजपाल सैनी भी अपने-अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे हैं। मौजूदा सांसद चंदन चौहान भी अपनी पत्नी के लिए जोर लगाए हैं।

उधर, सहयोगी दल भी सीट के बंटवारे को लेकर भाजपा के सामने अड़ंगा लगा रहे हैं। इसलिए भी बीजेपी के भीतर टिकट वितरण का मामला नहीं सुलझ पा रहा है। सरकार में कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद कटेहरी और मझवां सीट मांग रहे हैं तो रालोद भी मीरापुर के साथ ही खैर सीट पर दावेदारी जता रहा है। इसे लेकर भी भाजपा असमंजस में है। वैसे तो सभी सीटों पर दावेदारी के लिए रस्साकशी हो रही है, लेकिन भाजपा नेताओं के बीच असली जंग कटेहरी और मिल्कीपुर सीट के टिकट को लेकर है। इन दोनों सीटों पर अपने शागिर्दों व चहेतों को टिकट दिलाने के लिए कई मंत्री और संगठन के बड़े पदाधिकारी भी एड़ी-चोटी का जोर लगा रहे हैं। इससे शीर्ष नेतृत्व को टिकट तय करने में दिक्कत है रही है।मिल्कीपुर और कटेहरी सीट पर टिकट के लिए मारामारी ■ शेष पेज 04 पर

राजस्व विभाग में खाली पदों को भरेगी योगी सरकार

लखनऊ, संवाददाता।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लेखपाल, राजस्व निरीक्षक और नायब तहसीलदार के साथ-साथ लिपिकीय संवर्ग के सभी रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए तत्काल प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं।

श्री योगी ने कहा है कि तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक जैसे पदों के लिए जहां पदोन्नति लंबित है, वहां तत्काल प्रक्रिया पूरी की जाए। उन्होंने कहा है कि राजस्व विभाग सीधे तौर पर आम आदमी से जुड़ा हुआ है। आय, जाति और निवास प्रमाण पत्रों से लेकर पैमाइश, नामांकन, घरौनी, खतौनी, सर्वे, पट्टा सहित ढेरों महत्वपूर्ण प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण हो सके, इसके लिए न केवल विभाग के रिक्त पदों पर नई नियुक्ति की आवश्यकता है, बल्कि आवश्यकतानुसार नवीन पदों का सृजन किया जाए।

यही नहीं, उन्होंने राजस्व परिषद के अंतर्गत बन्दोबस्त आयुक्त (ग्रामीण) बन्दोबस्त आयुक्त (नगरीय) तथा निदेशक प्रशिक्षण ■ शेष पेज 04 पर

राहुल ने मिथुन नाई को भेजा सैलून का सामान

रायबरेली, एजेंसी।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के लालगंज में एक नाई को सैलून का सामान भेजा है। यह वही नाई है जहां श्री गांधी ने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान दाढ़ी और बाल कटवाए थे।पार्टी के जिलाध्यक्ष पंकज तिवारी ने शुक्रवार को बताया कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लालगंज के एक नाई 'मिथुन' को सैलून से सम्बंधित सामान भिजवाए है। सामान पाकर मिथुन बेहद खुश हुआ है। भेजे गए सामान की किट में एक शैम्पू चेयर, दो हेयर कटिंग चेयर के साथ एक इन्वर्टर बैटरी आदि शामिल है।लोकसभा चुनाव में प्रचार दौरान राहुल गाँधी ने मिथुन नाई के सैलून में अपनी शेव ट्रिम करवाई थी। बताते है कि राहुल गांधी के आने के बाद से मिथुन की दुकानदारी भी करीब चार गुना बेहतर चलने लगी है। यह सैलून रायबरेली के लालगंज के ब्रजेन्द्र नगर मोहल्ले में न्यू मुंबा देवी हेयर कटिंग सैलून के नाम से स्थित हैं।श्री राहुल गांधी के आने को याद करके मिथुन भावुक हो जाता है। वह कहता है कि जब श्री गांधी पहली बार उसकी दुकान पर आए तो वह एकबारगी घबरा गया था कि इतना बड़ा नेता उससे दाढ़ी बनवा रहा है। मिथुन ने अपनी दुकान पर राहुल गांधी की दाढ़ी बनवाते हुए फोटो भी लगाई हुई है।

मायावती का अखिलेश को जवाब, कहा- सफाई साबित करती है

अखिलेश हैं गठबंधन टूटने के जिम्मेदार

लखनऊ, एजेंसी।

मास्टर चाबी की बात फिर दोहराई

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) सुप्रीमो मायावती ने दोहराया है कि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी (सपा) के साथ गठबंधन टूटने की वजह खुद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव थे और यह उनके द्वारा दी जा रही सफाई से साबित भी होता है।

सुश्री मायावती ने एक्स पर पोस्ट किया लोकसभा चुनाव-2019 में यूपी में बसपा के 10 व सपा के पांच सीटों पर जीत के बाद गठबंधन टूटने के बारे में मैंने सार्वजनिक तौर पर भी यही कहा कि सपा प्रमुख ने मेरे फोन का भी जवाब देना बंद कर दिया था जिसको लेकर उनके द्वारा अब इतने साल बाद सफाई देना कितना उचित व विश्वसनीय। सोचने वाली बात। उन्होने कहा बीएसपी सैद्धान्तिक कारणों से गठबंधन नहीं करती है और अगर बड़े उद्देश्यों को लेकर कभी गठबंधन करती है तो फिर उसके ■ शेष पेज 04 पर

केजरीवाल की सशर्त जमानत पर बीजेपी बोली- हर सोमवार और गुरुवार होना होगा पेश, जेल वाला से अब

बेल वाला सीएम!

नयी दिल्ली, एजेंसी।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरविंद केजरीवाल को जमानत दिए जाने पर भाजपा नेता गौरव भाटिया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कट्टर बेईमान, आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल को फिर से आइना दिखाया है। जो आदेश पारित हुआ है, उसमें भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल को सशर्त जमानत मिली।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरविंद केजरीवाल को जमानत दिए जाने पर भाजपा नेता गौरव भाटिया ने कहा कि सशर्त बेल पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है है कि अन्य आरोपियों के जमानत आदेश की शर्तें अरविंद केजरीवाल पर भी लागू होंगी। अरविंद केजरीवाल का पासपोर्ट कोर्ट में रहेगा। वह विदेश यात्रा पर नहीं जा सकते हैं। अरविंद केजरीवाल को हर सोमवार और गुरुवार को जांच अधिकारी के सामने पेश होना पड़ेगा। वह गवाहों को डरा नहीं सकते और साक्ष्य को नष्ट नहीं कर सकते। भाटिया ने आगे इस बात पर जोर दिया कि केजरीवाल को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, उनका तर्क है कि मुख्यमंत्री का पद पर बने रहना भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को कमजोर करता है। कोर्ट में उनकी दलील थी कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है।

सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि अपीलकर्ता की गिरफ्तारी किसी भी अवैधता से ग्रस्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के दुष्प्रचार का भंडाफोड़ किया। अरविंद केजरीवाल को किसी भी अदालत से कभी राहत नहीं मिली और न ही कोई आरोप रद्द कर दिया गया है।भाटिया ने कहा कि आप को जवाब देना होगा कि ■ शेष पेज 04 पर

दिल्ली आबकारी नीति मामले में सुप्रीम कोट से राहत

केजरीवाल को मिली जमानत

नयी दिल्ली, एजेंसी।

उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली आबकारी नीति कथित घोटाले से संबंधित केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के मुकदमे में तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत देते हुए शुक्रवार को सशर्त जमानत दे दी।न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने श्री केजरीवाल की याचिका पर उन्हें यह राहत दी। दोनों न्यायाधीशों ने मुख्यमंत्री को 10 लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानती बौंड पर रिहा ■ शेष पेज 04 पर

बदलेगी बिलासपुर स्टेशन की तस्वीर!

बिलासपुर, एजेंसी।

रेल मंत्रालय के महत्वाकांक्षी परियोजना के अंतर्गत यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधा प्रदान करने हेतु अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत अंग्रेजों के जमाने की याद दिलाने वाले बिलासपुर (वर्तमान में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (एसईसीआर) मुख्यालय) रेलवे स्टेशन को 392 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्विकसित किया जा रहा है .

स्टेशन के पुनर्विकास में पुरानी ऐतिहासिक बिल्डिंग को पूर्ण रूप से संरक्षित रखा जाएगा, जिससे कि आधुनिक विकास के साथ-साथ पुरानी धरोहर भी सुरक्षित रहे। पुनर्विकास योजना का उद्देश्य यात्री सुविधाओं को उन्नत करना, भीड़ प्रबंधन में सुधार लाना और स्टेशन परिसर को आधुनिक बनाने के साथ-साथ इसे पर्यावरण के अनुकूल बनाना है। इसके तहत बेहतर प्रतीक्षालय, अत्याधुनिक सुरक्षा व्यवस्था, स्वच्छता और हरित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। योजना के तहत बिलासपुर शहर के दोनों किनारों पर उचित एकीकरण के साथ स्टेशन को सिटी सेंटर के रूप में विकसित करने तथा शहर को दोनों तरफ से जोड़ने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया गया है । स्टेशन भवन का डिजाइन छतीसगढ़ के स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला से प्रेरित होगा जिससे यह बिलासपुर शहर या स्थाटन की खूबसूरती को प्रदर्शित करेगी।

कॉनकोर्स में एकसाथ लगभग 800 यात्रियों के बैठने के लिए काफी बड़े प्रतिक्षालय का प्रावधान, 1150 से अधिक वाहनों के लिए लगभग 28 हजार वर्ग मीटर पार्किंग एरिया का प्रावधान, बेहतर भीड़ प्रबंधन हेतु स्टेशन में प्रवेश एवं निकास के अलग-अलग मार्ग का प्रावधान, तीन नए फुट चौड़े ओवरब्रिज का प्रावधान किया गया है जिसमें दो स्टेशन प्रवेश ■ शेष पेज 04 पर

सम्पादकीय

सीताराम येचुरी

एक महत्वपूर्ण आवाज खामोश हो गई

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के महासचिव सीताराम येचुरी नहीं रहे। 72 बरस की आयु में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली और इस तरह देश में लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहने वाली एक बुलंद आवाज शांत हो गई। हालांकि पचास बरसों से सुदीर्घ राजनैतिक जीवन में सीताराम येचुरी जिन मूल्यों के साथ काम करते रहे, उनकी गूंज बरसों-बरस बनी रहेगी, ऐसी उम्मीद है।सीताराम येचुरी भारतीय राजनीति के उन चंद महत्वपूर्ण नामों में से एक थे, जिन्होंने संसद से सड़क तक जनता के हितों की रक्षा और संवैधानिक मूल्यों के लिए राजनीति की। श्री येचुरी के लिए राजनीति दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाने का जरिया थी। सीताराम येचुरी एक बेहतरीन वक्ता थे और लगभग सभी दलों के साथ, वैचारिक मतभेदों के बावजूद उनके सौहार्दपूर्ण संबंध थे। संसद में उनके भाषणों को गौर से सुना जाता था। 1974 में स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी एसएफआई से उनके राजनैतिक जीवन की शुरूआत हुई, 1975 में वे सीपीएम के सदस्य बन गए। दिल्ली के सेंट स्टीफंस कॉलेज से स्नातक करने के बाद वे आगे की पढ़ाई के लिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में दाखिल हुए और यहां प्रकाश करात के साथ मिलकर वामपंथ का मजबूत गढ़ बनाने का काम उन्होंने किया। 1978 में श्री येचुरी एसएफआई के संयुक्त सचिव बने और 1979 में एसएफआई के अध्यक्ष बने। वे पहले अध्यक्ष थे, जो केरल या बंगाल के बाहर से थे।सीताराम येचुरी जब जेएनयू से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की पढ़ाई कर रहे थे, तभी इंदिरा गांधी सरकार ने 1975 में आपातकाल लगाया और उन्हें कई अन्य नेताओं के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था। इस वजह से उनकी पीएचडी अधूरी रह गई। जेल से बाहर आने के बाद सीताराम येचुरी जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए। 1992 में उन्हें पोलित ब्यूरो का सदस्य चुना गया। श्री येचुरी 32 वर्षों तक सीपीएम के पोलित ब्यूरो के सदस्य रहे। 2015 में वे पार्टी के महासचिव बने और इसके बाद 2018 फिर 2022 में इसी पद के लिए फिर से चुने गए। सीताराम येचुरी 2005 से 2017 तक राज्यसभा सांसद भी रहे।अपने सुदीर्घ राजनैतिक जीवन में सीताराम येचुरी ने आपातकाल से लेकर गठबंधन सरकारों के दौर देखे। 1996 में जब संयुक्त मोर्चा सरकार बनी, तब वे उन नेताओं में शामिल थे, जिन्होंने साझा न्यूनतम कार्यक्रम का मसौदा तैयार करने में अहम भूमिका निभाई थी। दरअसल श्री येचुरी ने पार्टी के दिवंगत नेता हरकिशन सिंह सुरजीत के मार्गदर्शन में काम सीखा था, जिन्होंने गठबंधन युग की सरकार में प्रमुख भूमिका निभाई थी। उनके निर्देशन में सबसे पहले वी पी सिंह की राष्ट्रीय मोर्चा सरकार और 1996-97 की संयुक्त मोर्चा सरकार बनी, दोनों ही सरकारों को माकपा ने बाहर से समर्थन दिया था। सीताराम येचुरी ने अपने कौशल को तब और निखारा जब वामपंथी दलों ने 2004 में पहली यूपीए सरकार का समर्थन किया और अक्सर नीति-निर्माण में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार पर दबाव डाला।आपातकाल में जेल जाने से लेकर कांग्रेस को सरकार बनाने तक सभी तरह के राजनैतिक उतार-चढ़ाव के साक्षी सीताराम येचुरी रहे हैं। इस देश के लोगों को वह तस्वीर याद है, जब जेएनयू की चांसलर पद से इंदिरा गांधी के हटने की मांग लेकर जेएनयू के छात्र उन्हीं के आवास के बाहर पहुंचे थे।

जे-के चुनावों के अनेक पहलू

> चुनाव आयोग के लिए 1962 के चुनाव कार्यक्रम को तय करने में सबसे बड़ी बाधा जम्मू-कश्मीर में मौसम था। दूसरी चुनौती यह थी कि इन चुनावों को पूरे भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों के साथ-साथ आयोजित किया जाये। हालांकि चुनाव आयोग ने महसूस किया कि बर्फ से ढंके राज्य में चुनाव कराने के लिए अप्रैल सबसे उपयुक्त महीना था।

18 सितंबर से 1 अक्टूबर, 2024 के बीच जम्मू और कश्मीर में दस साल बाद पहली बार विधानसभा चुनाव होंगे - 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के पांच साल बाद पहली बार।5 अक्टूबर को होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनावों के साथ-साथ जम्मू और कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों के लिए भी चुनाव हो रहे हैं, जो राज्य में 1962 के विधानसभा चुनावों के समान हैं - जो केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। 1962 के चुनाव उस साल फरवरी और अप्रैल के बीच देश भर में लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों के साथ-साथ हुए थे। स्वतंत्रता के बाद से जम्मू-कश्मीर का तीसरा चुनाव होने के बावजूद, 1962 के चुनाव भारत के चुनाव आयोग द्वारा पहली बार कराये गये थे।1962 से पहले, 1957 में जम्मू-कश्मीर के चुनाव या 1951 में संविधान सभा (जम्मू-कश्मीर का संविधान बनाने के लिए चुने गये प्रतिनिधियों का एक निकाय) के चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार नहीं था। 17 नवंबर, 1956 को संविधान सभा ने भारत के संविधान के तहत जम्मू-कश्मीर के संविधान को अपनाया। यह निर्णय 26 जनवरी, 1957 को लागू हुआ, जबकि पूरे भारत में आम चुनाव की तैयारी चल रही थी।हालांकि, 1957 में जम्मू-कश्मीर विधानसभा के चुनाव भी राज्य के संविधान के अनुसार ही हुए थे, लेकिन उनकी देखरेख सदर-ए-रियासत द्वारा नियुक्त चुनाव आयोग द्वारा की गयी थी। 26 जनवरी, 1960 को चुनाव कार्य को चुनाव आयोग को सौंपने के लिए राज्य के संविधान में संशोधन किया गया। जम्मू-कश्मीर 2024 में होने वाले चुनावों की तरह सुर्खियों में नहीं था। 71 रिटर्निंग ऑफिसर और 40 सहायक रिटर्निंग ऑफिसर चुनावों का प्रबंधन कर रहे थे, और 18 लाख से ज्यादा मतदाता थे।विधानसभा में सीधे चुनाव से 100 सदस्य थे, लेकिन 25 सीटें खाली रखी गयीं और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर के इलाके को परिसीमन से बाहर रखा गया।

दिलचस्प बात यह है कि पहले जम्मू-कश्मीर में 67 एकल-सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र और चार दो-सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र थे। लेकिन 1961 में, देश के दूसरे हिस्सों की तरह, दो-सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों को समाप्त कर दिया गया और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सिफ 'एक सदस्य वाली सीटों पर ही आरक्षण दिया गया।जम्मू-कश्मीर में भी चार दो-सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों को आठ एक-सदस्यीय सीटों में विभाजित कर दिया गया जिससे कुल सदस्य सीटों की संख्या 75 हो गयी।चुनाव आयोग के लिए 1962 के चुनाव कार्यक्रम को तय करने में सबसे बड़ी बाधा जम्मू-कश्मीर में मौसम था। दूसरी चुनौती यह थी कि इन चुनावों को पूरे भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों के साथ-साथ आयोजित किया जाये। हालांकि चुनाव आयोग ने महसूस किया कि बर्फ से ढंके राज्य में चुनाव कराने के लिए अप्रैल सबसे उपयुक्त महीना था, लेकिन जम्मू क्षेत्र में 24 फरवरी को मतदान हुआ, जबकि कश्मीर और लद्दाख क्षेत्रों ने 15 मार्च, 1962 को अपने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रयोग किया। यह निर्णय लिया गया कि पूरी चुनाव प्रक्रिया 31 मार्च से पहले पूरी कर ली जायेगी।1957 के विधानसभा चुनावों में, राज्य की प्रमुख राजनीतिक पार्टी जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस (जेकेएनसी) के उम्मीदवार 43 सीटों पर निर्विरोध चुने गये। उस चुनाव में 75 विधानसभा सीटों में से जेकेएनसीने 69, प्रजा परिषद ने पांच और हरिजन मंडल ने एक सीट जीती। जेकेएनसी का चुनाव चिन्ह कांग्रेस जैसा ही था- एक जूआ ढोने वाले बैलों की जोड़ी। प्रजा परिषद का चुनाव चिन्ह उगता हुआ सूरज था, जबकि हरिजन मंडल का चुनाव चिन्ह खड़ा हुआ शेर था।1962 के चुनावों में, जेकेएनसी के उम्मीदवार 34 सीटों पर निर्विरोध चुने गये। 41 अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में 140 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। इन 41 सीटों में से जेकेएनसी ने 36, प्रजा परिषद ने तीन और दो निर्दलीय उम्मीदवारों ने शेष दो सीटें जीतीं। अन्य दलों की जमानतें जब्त हो गयीं। चार निर्वाचन क्षेत्रों में कुछ मतदान केंद्रों में गंभीर अनियमितताओं के आरोपों के कारण नये सिरे से चुनाव कराने का आदेश दिया गया। मतदाता सूची और 1,223 मतदान केंद्रों की स्थापना सहित चुनाव पर राज्य द्वारा किया गया खर्च केवल 2,92,649 रुपये था जेकेएनसी के चुनावों में जीत के साथ, जम्मू-कश्मीर के पीएम बख्शी गुलाम मोहम्मद राज्य का नेतृत्व करते रहे। हालांकि, ये चुनाव विवादों से अछूते नहीं रहे। कुछ विपक्षी दलों ने चुनावों का बहिष्कार करने की धमकी दी। आरोप लगाया गया कि ये 'स्वतंत्र और निष्पक्ष' नहीं थे। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और जीएम सादिक की वामपंथी डेमोक्रेटिक नेशनल कॉफ्रें स ने एक संयुक्त बयान जारी कर कहा था कि 'सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रांतीयवाद और क्षेत्रवाद की भावना को हवा दे रही है' और घोषणा की कि वे चुनावों का बहिष्कार कर रहे हैं। हालांकि, पीएसपी ने छह सीटों पर और डीएनसी ने 20 सीटों पर चुनाव लड़े, दोनों एक भी सीट हासिल करने में असफल रहे।

पेरिस पैरालंपिक के संदेश को समझना जरूरी

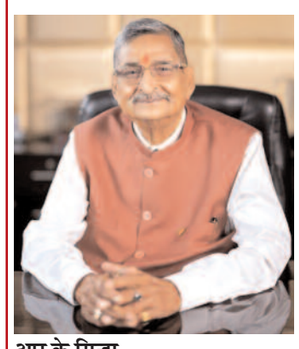

आर.के.सिन्हा

पेरिस में ओलंपिक खेलों में लचर प्रदर्शन के बाद पैरालंपिक में भारतीय एथलीटों के प्रदर्शन से सारा देश खुश है। हमारे एथलीटों ने अपने उल्लेखनीय और शानदार अविश्वसनीय प्रदर्शन से देश का मान बढ़ाया है। इन दिव्यांग खिलाड़ियों ने शारीरिक चुनौतियों का सामना करने के बावजूद अपने उल्लेखनीय खेल से हरेक भारतीय प्रेरित किया है। भारत ने पैरालंपिक में 29 पदकों (सात स्वर्ण, नौ रजत और 13 कांस्य) जीते, जो कि अबतक का एक रिकॉर्ड है। इसमें कोई शक नहीं है कि पदक तालिका में भारत का 18वां स्थान, सरकार द्वारा दिव्यांग खिलाड़ियों को दिए जाने वाले प्रोत्साहन और सुविधाओं में बढ़ोत्तरी का ही प्रमाण है। इस पैरालंपिक में भारतीय कोचों और सहायक कोच भी पेरिस में खिलाड़ियों को हर तरह के सहयोग के लिए पर्याप्त संख्या में मौजूद थे। पहली बार भारतीय एथलीटों के लिए खेल गांव में एक स्पेशल रिकवरी सेंटर बनाया गया था। इससे खिलाड़ियों को चोटों से उबरने और अपनी फिटनेस को तेजी से सुधारने में मदद मिली, जिससे वे अपने प्रदर्शन में निरंतरता बनाए रख सके।भारत ने पेरिस पैरालंपिक में 77 कोच और सहयोगी स्टाफ भेजे, जो टोक्यो पैरालंपिक में भेजे गए 45 कोच और सहयोगी स्टाफ से कहीं ज्यादा थे। इससे खिलाड़ियों को बेहतर मार्गदर्शन और देखभाल मिली, जिसका सीधा असर उनके प्रदर्शन पर पड़ा। पैरालंपिक में देश की भागीदारी ने केवल 16 वर्षों में एक उल्लेखनीय छलांग लगाई है। 2008 में बीजिंग पैरालंपिक में पाँच एथलीटों के मुकाबले अब भारतीय दल 84 हो गया है। बीते रविवार को खेलों की समाप्ति से पहले भारत के पैरालंपियनों ने एक भारतीय रेस्तरां में सुस्वादु भोजन का आनंद भी लिया। हमारे खिलाड़ी जश्न के मूड में थे। ये जश्न मनाने के हकदार भी थे।यदि 2021 के टोक्यो पैरालंपिक में ही भारत ने संकेत दे दिए थे कि अब भारत पैरा स्पोर्ट्स के शिखर पर जाने को बेताब है।तो 2024 के पेरिस पैरालंपिक उस ख्वाब को भी हमारे दिव्यांग खिलाडियों ने काफी तक सच भी साबित कर दिया। एक दौर था जब भारत इन खेलों में दो-चार पदक ही ले पाता था। पर अब वह दिन चले गए। भारत अब दो अंकों में पदक हासिल कर रहा है और आसानी से अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ रहा है।बेशक, पिछले टोक्यो खेलों में भारत के 19 पदक के प्रदर्शन ने देश में पैरालंपिक खेलों को बढ़ावा देने की दिशा में एक लंबी छलांग लगाई थी। इस अर्थ में, पेरिस में यह देखना था कि क्या भारत इन खेलों में तेजी से आगे बढ़ रहा है अथवा नहीं। पैरालंपिक में हमारे श्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ ही देश और समाज को दिव्यांगों के प्रति अधिक उदार और मानवीय रवैया अपनाना होगा।अभी भी दिव्यांगों के हक में बहुत कुछ किया जाना शेष है। क्या हमारे देश में दिव्यांगों विकलांगों के मन-माफिक घरों या कमर्शियल इमारतों का निर्माण हो रहा है? कतई नहीं। अब लक्जरी होम, सी-फेसिंग फ्लैट, एलिट होम वगैरह के दौर में कितने बिल्डर और आर्किटेक्ट रीयल एस्टेट कंपनियों को उंगुलियों पर गिना जा सकता है जो दिव्यांगो तथा बुजुर्गों की सुविधा का ध्यान रखकर निर्माण कर रही हैं। अब उदाहरण के लिए आपको इस तरह की आवासीय और कमर्शियल इमारतें कम ही मिलेंगी जिनमें विकलांगों की व्हीलचेयर को लिफ्ट के अंदर लेकर जाया जा सकता है। लिफ्ट में इतना कम स्पेस रहता है कि व्हीलचेयर को उसके अंदर लेकर जाना मुमकिन नहीं होता। बाथरूम और किचन में कैबिनेट इतनी ऊंचाई में होते हैं कि दिव्यांग शख्स के लिए उनका इस्तेमाल करना बेहद कठिन होता है। इस तरह के मसलों को देखने की जरूरत है। अमेरिका में उन्हीं रियलटर्स को दिव्यांगों को घर मुहैया करवाने की इजाजत दी जाती है, जो इसके लिए योग्य और प्रशिक्षित हैं लेकिन, भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है।

भारत में मानसिक और शारीरिक तौर पर विकलांग लोगों को रोजाना किसी न किसी तरह के भेदभाव का सामना करना ही पड़ता है। 2011 के आंकड़ों के मुताबिक भारत में करीब दो करोड़ 60 लाख विकलांग हैं। हालांकि गैर-सरकारी संगठनों के मुताबिक इनकी संख्या और बढ़ी है और यह छह और सात करोड़ के बीच हैं। संबंधित सरकारी महकमों को सुनिश्चित करना चाहिए ताकि बिल्डर और आर्किटेक्ट दिव्यागों के मन-माफिक ही इमारतें खड़ी करें। दिव्यांगों को देश के बाकी नागरिकों की तरह देखा जाना चाहिए। उन्हें अहसानों की जरूरत तो नहीं पर सामाजिक सम्मान के वे अवश्य ही हकदार हैं। पेरिस पैरालंपिक के विजेताओं को भी उसी तरह से पुरस्कृत किया जाये, जैसे ओलंपिक खेलों के विजेता हुए हैं देश में 16 किस्म की मान्य विकलांगता वें हैं। विकलांगों के आवास के लिए विशेष योजना बनाने की जरूरत है। व्हीलचेयर पर चलने वाली आबादी का मानना है कि कहीं भी प्रवेश की अगमता सुविधा होना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

एक विकलांग व्यक्ति को अपने घर से बाहर लाने, कॉलेज या दफ्तर जाने के लिए, बस पकड़ने, शॉपिंग कांप्लेक्स जाने या अन्य सार्वजनिक इमारतों में प्रवेश की वैसी ही सुविधा होनी चाहिए, जैसी सामान्य लोगों के लिए होती है। देश में स्थिति यह है कि अधिकतर स्थानों पर विकलांग व्यक्ति आसानी से जा ही नहीं सकते हैं।अगर पश्चिम की देशों की बात करें तो वहां पर सार्वजनिक भवनों के गेट बहुत भारी-भरकम नहीं होते, जिससे कि व्हीलचेयर पर बैठा व्यक्ति भी बिना किसी अन्य सहायता के स्वयं ही सुगमता से आ-जा सकता है। सभी प्रसाधन स्थान भी इन सुविधाओं को ध्यान में रख बनाए गए हैं। लिफ्ट में खासतौर पर ऑपरेशनल स्विचों को नीचे की तरफ लगाया जाता है, जिससे विकलांग व्यक्ति को परेशानी का सामना न करना पड़े। पेरिस पैरालंपिक देश के लिए एक संदेश भी है कि हमें दिव्यांगों को उनके हकों को देना ही होगा।

श्रीलंका में 21 सितंबर को हो रहा राष्ट्रपति चुनाव भारत के लिए महत्वपूर्ण

श्रीलंका में 21 सितंबर, 2024 को राष्ट्रपति चुनाव होंगे, जिसमें 220 लाख की कुल आबादी में से 170 लाख लोग मतदान करेंगे। विदेशी समाचार विश्लेषकों का मानना है कि श्रीलंका 'नयी दृष्टि, साहसिक सुधार और स्थिर नेतृत्व' का चयन करेगा। कुल 38 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे भी शामिल हैं, जो एक स्वतंत्र उम्मीदवार हैं। विक्रमसिंघे ने खाद्यान्न, ईंधन, रसोई गैस और दवा की सामान्य आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कठोर मितव्ययिता उपाय लागू किये और करों में वृद्धि की, और उन्हें उम्मीद है कि मतदाता उन्हें देश की अर्थव्यवस्था को सामान्य स्थिति में लाने के लिए एक और मौका देंगे।हालांकि, छह बार प्रधानमंत्री रह चुके विक्रमसिंघे को पुरानी पीढ़ी के उन राजनेताओं में से एक माना जाता है, जिन्हें मौजूदा आर्थिक गड़बड़ियों के लिए स्वयं को भी जिम्मेदार मानना चाहिए।विक्रमसिंघे के लिए मार्क्सवादी गठबंधन, नेशनल पीपुल्स पावर के नेता अनुरा कुमारा दिसानायके एक प्रमुख चुनौती बनकर उभरे हैं।

एक अन्य चुनौती विक्रमसिंघे की पार्टी, यूनाइटेड पीपुल्स पावर के सजित प्रेमदासा हैं। विभाजन के बाद, प्रेमदासा, जो राष्ट्रपति विक्रमसिंघे के डिप्टी थे, अब इस पार्टी के नेता हैं। वह श्रीलंका के राष्ट्रपति चुनाव में एक और उम्मीदवार हैं। राजपक्षे वंश से, महिंद्रा राजपक्षे के बेटे नमिल राजपक्षे चुनाव लड़ रहे हैं। इन चार नेताओं में से एक के श्रीलंका के अगले राष्ट्रपति के रूप में उभरने की उम्मीद है।जबकि इन उम्मीदवारों ने अपनी आर्थिक प्राथमिकताओं को रेखांकित किया है, सीमित संसाधनों और भारी बाहरी ऋणों के सामने पैंतरेबाजी के लिए सीमित जगह को देखते हुए, उनके चुनावी वायदों को शायद ही गंभीरता से लिया जाता है। जबकि दिसानायके उन युवाओं के बीच लोकप्रिय हैं जो एक कुशल और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चाहते हैं, प्रेमदासा अल्पसंख्यक तमिल वोटों पर भरोसा कर रहे हैं, और विक्रमसिंघे ने हाल ही में मुस्लिम वोटों पर नजर रखते हुए एक मुस्लिम मंत्री को नियुक्त किया है। जबकि हर कोई चाहता है कि भ्रष्टाचार खत्म हो और अर्थव्यवस्था की सामान्य स्थिति बहाल हो, कोई भी केंद्रीय मुद्दा चुनाव पर हावी नहीं है।पूर्व वित्त मंत्री एरन विक्रमरत्ने का कहना है कि श्रीलंका में सबसे बड़ी समस्या अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि कानून के शासन की अनुपस्थिति है। 'यदि कानून का शासन कायम रहता है और हर नागरिक को लगता है कि कानून सभी पर समान रूप से लागू होता है, चाहे वह किसी भी स्थिति, शक्ति या धन का हो, तो हर नागरिक सम्मान के साथ रह सकता है। यह जानकर कि कानून काम करता है, विदेशी निवेशकों को इस देश में निवेश करने के बारे में विश्वास मिलेगा। साजिथ प्रेमदासाके एसजेबी ब्लूप्रिंट - समागी जन बलवेगया (एसजेबी) - के अनावरण के अवसर पर बोलते हुए मैंने दोहराया कि एसजेबी सरकार कानून के शासन को बनाये रखेगी और बढ़ावा देगी, अर्थव्यवस्था को वास्तविक सुधार और तीव्र विकास की ओर ले जाएगी,' उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा।श्रीलंका के सरकारी कर्मचारियों और सैन्य कर्मियों ने डाक से अपने वोट डालना शुरू कर दिया है। लगभग 700,000 सरकारी कर्मचारी वोट देने के पात्र हैं।हिंद महासागर में अपनी रणनीतिक स्थिति के कारण, अंतरराष्ट्रीय शक्तियां श्रीलंका में प्रभाव के लिए होड़ करती हैं। पड़ोसी क्षेत्रीय शक्तियां भारत और चीन अक्सर इस द्वीप राष्ट्र में प्रभाव के लिए प्रतिस्पर्धा करते देखे जाते हैं। जबकि चीन ने कई बुनियादी ढांचा परियोजनाएं बनायीं और हंबनटोटा बंदरगाह और लगभग 15,000 एकड़ जमीन 99 साल के पट्टे पर हासिल की, भारत ने आर्थिक संकट के दौरान 4अरब डॉलर से अधिक का निवेश किया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह बाहरी ऋणों, ज्यादातर चीनी के बोझ तले दब न जाये।

> भारत और चीन के अलावा, अमेरिका और यूरोपीय संघ सहित कई अन्य देश और ब्लॉक, श्रीलंका में इसके रणनीतिक स्थान के कारण प्रभाव डालने के इच्छुक हैं। लगभग 80प्रतिशत अंतरराष्ट्रीय कार्गो इस क्षेत्र से होकर गुजरता है, और श्रीलंका में मजबूत आधार रखने वाला कोई भी व्यक्ति सत्ता समीकरणों को अपने पक्ष में झुका सकता है।

महिंद्रा राजपक्षे (2005-2015) के शासनकाल के दौरान, श्रीलंका ने चीनी ऋणों द्वारा वित्तपोषित कई महंगी अवसंरचना परियोजनाएं शुरू कीं, जिन्हें कई लोग सफेद हाथी मानते हैं, जो किसी वास्तविक उद्देश्य की पूर्ति नहीं करते।भारत और चीन के अलावा, अमेरिका और यूरोपीय संघ सहित कई अन्य देश और ब्लॉक, श्रीलंका में इसके रणनीतिक स्थान के कारण प्रभाव डालने के इच्छुक हैं। लगभग 80प्रतिशत अंतरराष्ट्रीय कार्गो इस क्षेत्र से होकर गुजरता है, और श्रीलंका में मजबूत आधार रखने वाला कोई भी व्यक्ति सत्ता समीकरणों को अपने पक्ष में झुका सकता है। इस कारण से, अंतरराष्ट्रीय शक्तियां श्रीलंका के चुनाव पर कड़ी नजर रखेंगी और जीतने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयास करेंगी।चूंकि श्रीलंका की अर्थव्यवस्था अभी भी अनिश्चित स्थिति में है, इसलिए राष्ट्रपति चुनाव जीतने वाले किसी भी व्यक्ति को इस बारे में अधिक स्वतंत्रता नहीं है कि वे आर्थिक या अंतरराष्ट्रीय नीतियों को कैसे लागू करना चाहते हैं। श्रीलंका ऋणदाताओं और दाताओं के दबाव में रहेगा।

मोदी का सीजेआई के घर जाना राहुल-अखिलेश को अखर गया: गिरिराज

प्रयागराज, संवाददाता।

केन्द्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का गणेश पूजा में मुख्य न्यायाधीश के घर जाना कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी (सपा) मुखिया अखिलेश यादव को रास नहीं आया।नैनी में महेवा स्थित क्रॉफ्ट टूरिज्म विलेज के उद्घाटन के मौके पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होने कहा ह्ल श्री मोदी देश के मुख्य न्यायाधीश के घर गणेश पूजन में गए तो टुकड़े-टुकड़े गैंग को अच्छा नहीं लगा। ये टोपी पहनने के लिए हामिद के यहां जाएंगे तो अच्छा लगता है। अगर आतंकवादियों के लिए रात में अदालत के दरवाजे खुलते हैं तो केजरीवाल, अखिलेश यादव और राहुल गांधी को अच्छा लगेगा।

यदि न्यायाधीश (जज) के यहां कोई गणेश पूजन के लिए जाए तो इन्हें रास नहीं आता है।उन्होंने कहा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आजकल महंतों को गाली दे रहे हैं। गोरखपुर पीठ को गाली दे रहे हैं। उन्हे पता होना चाहिये कि काठ की हांडी बार-बार नहीं चढ़ती। ये 1976 का माहौल बनाना चाहते हैं। जनता अब दोबारा इस देश में तानाशाह को पनपने नहीं देगी।अखिलेश यादव के विवादित टिप्पणी मठाधीश और माफिया में ज्यादा फर्क नहीं पर प्रतिक्रिया देते हुए केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि उन्हें अपराधियों में भी जाति दिखाई पड़ती है उन्होंने अपने कार्यकाल में जाति देखी और गुंडागर्दी को बढ़ावा दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपराधी केवल अपराधी नजर आता है।

यही योगी और अखिलेश में अंतर है। योगी के कार्यकाल में अपराधी या तो घर में छिप गये या फिर ऊपर गए।श्री सिंह ने कहा कि हिमाचल के हिंदुओं ने एकजुटता का प्रदर्शन किया। ये संदेश हिमाचल पूरी दुनिया को देता है कि अगर हिंदू एकजुट रहेंगे तो न तो कोई गोरा आएगा न/न मुगल। हिमाचल के हिंदुओं की एकजुटता का संदेश पूरे देश में फैलाना चाहिए। इसी एकजुटता की देश को आवश्यकता है।उन्होंने कहा यह देश का दुर्भाग्य है कि विपक्ष के नेता विदेश में जाकर यहां की झूठी आलोचना कर रहे हैं। तेजस्वी यादव बिहार में रहकर झूठ बोल रहे और गाली दे रहे हैं।देश की जनता सब जान चुकी है। अब तानाशाह सरकार को सत्ता नहीं सौंपना है।एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि केजरीवाल भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद थे। जमानत पर बाहर आए हैं। उनका केस नहीं खत्म हुआ है। एक मंत्री जेल से छूटा तो 10 लोगों को लेकर गली-गली घूम रहे हैं, लग रहा है जैसे आजादी की लड़ाई लड़कर आए हैं। केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ शपथ लिया था, अपने लड़के का कसम खाया था लेकिन आज उसकी पूरी सरकार भ्रष्टाचार के दलदल में है।

कानपुर: रूमा औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करेगा यूपीसीडा

कानपुर, संवाददाता।

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक प्राधिकरण (यूपीसीडा) कानपुर के रूमा औद्योगिक क्षेत्र को अटल औद्योगिक अवसंरचना मिशन के तहत आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करेगा। अधिकृत सूत्रों ने बताया कि कानपुर के प्रमुख औद्योगिक केंद्र रूमा औद्योगिक क्षेत्र को अटल औद्योगिक अवसंरचना मिशन के तहत आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। यह क्षेत्र 2004-05 में स्थापित हुआ था।यूपीसीडा के सीईओ मयूर माहेश्वरी ने बताया कि रूमा औद्योगिक क्षेत्र दिल्ली-हावड़ा रेलवे लाइन और कानपुर-प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 के बीच में स्थित है।

यह कानपुर शहर के नजदीक है और लखनऊ से मात्र 80 किमी दूर है। साथ ही चकेरी हवाई अड्डे से नजदीकी इसके लॉजिस्टिक महत्व को और बढ़ा देती है। रूमा औद्योगिक क्षेत्र की औद्योगिक संरचना को आधुनिक बनाने और सुधारने के लिए 90 करोड़ का बजट रखा गया है। परियोजना वित्तीय मूल्यांकन डिवीजन ने इस पहल के लिए 86 करोड़ रुपये का बजट तय किया है, जिससे इस क्षेत्र में कई सुधार किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र में लगभग 9.76 किमी सड़कों का उन्नयन किया जाएगा। इस परियोजना में 796 मीटर मैकेनिकल, इंजीनियरिंग और प्लंबिंग सिस्टम और पक्के फुटपाथ का निर्माण भी शामिल है।साथ ही, जल प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए, सड़कों के किनारे 35 पुलिया और 18.83 किमी जल निकासी लाइनें बनाई जाएंगी। इसके अलावा एक व्यापक सीईटीपी परिवहन प्रणाली लागू की जाएगी, जिसमें 11.21 किमी सीईटीपी परिवहन पाइपलाइनें शामिल होंगी, जिसमें 250 मिमी व्यास वाली 10.51 किमी लाइनें और 341 मैनहोल के साथ 300 मिमी व्यास वाली 0.70 किमी लाइनें शामिल होंगी। माहेश्वरी ने बताया कि इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड में 21.32 किमी लंबी पानी की पाइपलाइन बिछाना, एक नए ट्यूबवेल की स्थापना और मौजूदा बुनियादी ढांचे की मरम्मत शामिल होगी। इसके अतिरिक्त क्षेत्र की जरूरतों को बेहतर ढंग से समायोजित करने के लिए मौजूदा 0.75 एमएलडी सीईटीपी के अलावा 3.00 एमएलडी क्षमता वाला एक नया सीईटीपी प्लांट लगाया जाएगा। वहीं, रूमा औद्योगिक क्षेत्र में उद्यमियों और श्रमिकों के लिए नई सुविधाओं का विकास किया जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए ईवी चार्जिंग सेंटर और क्षेत्र की सुरक्षा व पहुंच बेहतर करने के लिए तीन नए प्रवेश द्वार शामिल हैं। यात्रियों और कार्यबल की सुविधा के लिए बस शेल्टर, पक्षियों के आश्रय के लिए बर्ड शेल्टर, और बाहरी क्षेत्र की सुंदरता बढ़ाने के लिए स्ट्रीट फर्नीचर को भी सम्मिलित किया गया है।

इसके साथ ही, संचालन की कुशल निगरानी के लिए स्टेट ऑफ आर्ट इंटीग्रेटेड कण्ट्रोल और कमांड सेण्टर तैयार किया जाएगा। बेहतर सुरक्षा के लिए उन्नत सीसीटीवी सिस्टम लगाए जाएंगे और कॉमन फैसिलिटी सेंटर (सीएफसी) को भी अपग्रेड किया जाएगा। 63,000 वर्ग मीटर की घास इस क्षेत्र को सुशोभित करेगी और इसके हरित आवरण को बढ़ाएगी। कचरा प्रबंधन क्षेत्र की स्वच्छता बनाए रखने के लिए व्यापक कचरा प्रबंधन किया जाएगा। प्रवेश सड़कों और पार्कों के किनारे बागवानी, प्लांटर्स, पार्कों की सजावट और विकास, सिंचाई सिस्टम, जल आपूर्ति, वर्षा जल संचयन, जल निकासी प्रणालियाँ और ग्रीन बेल्ट स्थापित किए जाएंगे।

लखनऊ में ठग गिरोह का पदार्फाश, एक गिरफ्तार

लखनऊ, संवाददाता।

उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने एक शातिर ठग गिरोह का पदार्फाश किया है जो स्वयं को मुख्यमंत्री का निजी सचिव बताकर,प्रतियोगी परीक्षाओं में पास कराने का झांसा देकर और ऑनलाइन गैंबलिंग के जरिये लोगों को चूना लगाता था। पुलिस ने गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि आजमगढ़ के निजामाबाद क्षेत्र के निवासी फारूख अमन (26) को बीती रात करीब 12 बजे अवध बस स्टैंड के पास से धर दबोचा गया।पूछताछ मे फारूख ने बताया कि उसने कर्नाटक से बी-फार्मा किया है। उसकी वर्ष 2021 से स्ट्रीमकार-लाइव स्ट्रीम व चैट कंपनी में दो एजेंसी हैं, जिसमें लगभग 125 होस्ट है। फरवरी 2024 में उसकी मुलाकार ह्यठाकुरह्ल नामक एक सेंडर से हुयी जिसने खुद का परिचय मुख्यमंत्री के निजी सचिव के तौर पर दिया। इसके बाद फारूख की स्ट्रीमकार/व्हाट्सएप पर ठाकुर से बात होने लगी। कुछ दिन सम्पर्क मे रहने के बाद फारूख को पता चला कि ठाकुर अधिकारी नही है। इसके कुछ दिन बाद कथित निजी सचिव को हवाला के माध्यम से कुछ रुपए किसी से लेने थे। तब फारूख ने उसके व्हाट्सएप अकाउंट को दूसरे के फोन में स्कैन करके कैसे लागिन करते हैं यह बताया था।काम होने पर कथित निजी सचिव ने फारूख के कहने पर फारूख की स्ट्रीमकार आईडी पर लाखों रुपए के क्वाइन गिफ्ट किया था। जिससे फारूख लालच में आ गया और उसके साथ मिलकर ठगी का काम करने लगा। फारूख कथित निजी सचिव को अपने होस्टों की आईडी भेजकर क्वाइन सेंडिग कराता था। कथित निजी सचिव के रिचार्ज कराने से व होस्टों को सेंडिग करने से फारूख को 14 प्रतिशत, कम्पनी को 26 प्रतिशत व होस्ट को 60 प्रतिषत कमिशन मिलता था।

26 जुलाई को कथित निजी सचिव ने व्हाट्सएप पर पुलिस भर्ती से सम्बन्धि स्टोरी लगाया था, जिस पर फारूख ने उसने पूछा तब उसने बताया कि अगर किसी को भर्ती कराना हो तो मैं सात लाख में करा दूगा उसमे से हम लोगों का आधा आधा हो जायेगा आज उसी के कहने पर ही फारूख लखनऊ आया था।फारूख ने बताया कि स्ट्रीमकार एक लाइव स्ट्रीमिंग, चैटिंग एण्ड गैम्बलिंग एप है। इस एप पर ऑनलाइन गैंबलिंग तीन पत्ती, टेजर हंट, अलीबाबा, डर्बी, फ्रूटलुक हैं। कम्पनी द्वारा जो जुआ कराया जाता है उसमें लोग जो रिचार्ज लेते है उसका सात प्रतिशत कमीशन फारूख को मिलता है।

खास खबर

नीम टीकर ग्राम सभा में ग्राम चैपाल का आयोजन

बछरावां रायबरेली। बछरावां ब्लॉक क्षेत्र के नीम टीकर ग्राम सभा में शुक्रवार दोपहर ग्राम चैपाल का आयोजन किया गया।इसकी अध्यक्षता खुद खंड विकास अधिकारी शिव बहादुर सिंह ने की।ग्राम चैपाल के समय ग्रामीण तथा ग्राम प्रधान नीलम वर्मा मौजूद रही।खंड विकास अधिकारी शिव बहादुर सिंह ने ग्रामीणों से आवास में आ रही दिक्कतों के बारे में जाना और प्रार्थना पत्र लिया शौचालय का पैसा रुका होने पर भी प्रार्थना पत्र लिया गया जिन किसानों का प्रधानमंत्री किसान सम्मन निधि के बारे में हकीकत जानते हुए जिन भी किसानों का पैसा उनके बैंक खाते में नहीं पहुंच रहा.

बाल विकास परियोजना अधिकारी पुरवा की अध्यक्षता में पोषण रैली का हुआ आयोजन

पुरवा। शुक्रवार को तहसील परिसर से बाल विकास परियोजना पुरवा के अंतर्गत संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों पर माह 1 सितंबर 2024 से 30 सितंबर 2024 तक मनाये जा रहे पोषण माह के उपलक्ष में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के द्वारा बाल विकास परियोजना अधिकारी पुरवा की अध्यक्षता में पोषण रैली का आयोजन किया गया उपजिलाधिकारी श्री उदित नारायण सेंगर द्वारा हरी झंडी दिखाकर रैली का शुभारम्भ किया गया रैली में तहसीलदार श्रीमती साक्षी राय, बाल विकास परियोजना अधिकारी श्री दिनेश प्रजापति, खंड विकास अधिकारी श्री संतोष कुमार श्रीवास्तव, समस्त मुख्य सेविका, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर एवं आंगनबाड़ी कार्यत्रियों के द्वारा प्रतिभाग किया गया.

घास काटने गई महिला जंगली जानवर के हमले में घायल

लालगंज रायबरेली। कोतवाली क्षेत्र के जगतपुर रामगढ़ी गांव निवासिनी एक महिला पर बुधवार की शाम एक जंगली जानवर ने हमला बोल दिया। जिससे वह जख्मी हो गई। उसने अपना इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया है। महिला ने चिकित्सीय स्टाफ से बताया कि बुधवार की शाम को वह खेतों में घास काटने के लिए गई थी। तभी किसी तेंदुए की शक्ल वाले जानवर ने पीछे से आकर उसका हाथ अपने मुंह में भर लिया। उसने जोर का झटका देकर शोर मचाया तो वह वहां से भाग गया। महिला भोला देवी (50) पत्नी लक्ष्मीशंकर का दावा है उस पर तेंदुए ने हमला किया है।

मोहनलाल गंज के एस.डी.वी.अकैडमी स्कूल में चलाया गया नि:शुल्क डेन्टल मेडिकल कैम्प

सत्ता संकेत
संवादादात दीपक विमल।

लखनऊ।आपको बता दें कि लखनऊ जनपद के मोहनलाल गंज ब्लाक के अन्तर्गत रानी खेड़ा में श्री हरदेव लाल सेवा संस्थान के तत्वावधान में एस.डी.वी.अकैडमी में दिनांक 13/9/2024नि:शुल्क डेन्टल मेडिकल कैम्प बच्चों के दातों का चेकअप साथ ही दातों की साफ सफाई के बारे में जानकारी दी गायी साथ ही 150 बच्चों को कैसे दातों में ब्रश करना चाहिए जानकारी दिया किस तरीके से साफ सफाई करना चाहिए जिससे हमारे दांतों में कीड़े ना लगे डॉक्टर प्रोफेसर गुंजन यादव, डॉक्टर गरिमा चौधरी डेन्टल हॉस्पिटल टीम की उपस्थिति में नि:शुल्क दातों की सफाई और चेकअप,किया गया डेन्टल हॉस्पिटल लखनऊ द्वारा कार्य स्थल :- एस.डी.वी.अकेडमी रानीखेड़ा डेहवा मोहनलालगंज लवकुश यादव प्रधान/प्रबंधकमण्डल अध्यक्ष लखनऊ मण्डल उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ।

शोभायात्रा निकाल कर गणपति बप्पा की प्रतिमा का धूमधाम से हुआ विसर्जन

सत्ता संकेत
संवादादात दीपक विमल।

मोहनलालगंज-लखनऊ। नगर पंचायत मऊ स्थित सिद्ध पीठ दुर्गा माता मंदिर में आयोजित श्री गणेश उत्सव की प्रतिमा का शुक्रवार को भौरेश्वर बाबा मंदिर निकट सई नदी में विसर्जन कर दिया गया। मोहनलालगंज नगर पंचायत मऊ बाजार में स्थित सिद्ध पीठ प्राचीन दुर्गा माता मंदिर में श्री गणेश चतुर्थी से आयोजित हुए श्री गणेश उत्सव में भक्तों ने भजन कीर्तन के साथ मनौती के राजा श्री गणेश जी को अनेकों प्रकार के भोग अर्पित करते हुए प्रतिदिन भजनों के माध्यम से अपने दिल की बातो के साथ भजनों के माध्यम से संपन्नता आशीर्वाद का कार्यक्रम चलता रहा, शुक्रवार सुबह वैदिक मंत्रोचारण के साथ विधि विधान से आचार्य रमेश मिश्र ने पूजन कराया और उसके बाद भक्तगण श्री गणेश जी की प्रतिमा को बग्घी पर लेकर पूरे गांव में भ्रमण करते हुए गाजे बाजे के

साथ डांस करते हुए निकले और प्रसाद वितरण करते हुए मोहनलालगंज पहुंचे जहां पर गौरव पांडेय , विनय पांडेय ने श्री गणेश जी को नमन किया और उसके बाद सभी भक्तों ने गणेश जी की प्रतिमा को लेकर भवरेश्वर बाबा मंदिर प्रांगण पहुंचे सई नदी की अविरल धारा में विसर्जन कर दिया गया।

वही सई नदी में प्रत्येक वर्ष भक्तगण श्री गणेश जी की प्रतिमा को ले जाकर इसी सई नदी की अविरल धारा में विसर्जित करते है सोमवार को प्रतिमा विसर्जन के दौरान भक्तों ने खूब भजन गाए और रंग-बिरंगे गुलाल रंगों से खेलते हुए भौरेश्वर बाबा मंदिर प्रांगण में पहुंचे और सई नदी की अविरल धारा में प्रतिमा का विसर्जन करने के उपरांत भक्तों ने भवरेश्वर बाबा मंदिर में पहुंचकर भगवान शिव के शिवलिंग पर माथा टेकते हुए भौरेश्वर बाबा से आशीर्वाद प्राप्त किया।

इस मौके पर गणेश उत्सव समिति योगेश गुप्ता, शैलेंद्र सोनी ,संदीप गुप्ता सहित भक्तगण सूरज गुप्ता,मिंटू, छोटू गुप्ता , वरिष्ठ पत्रकार शिव बालक गौतम,अनुज,अनूप पांडे , ललित गुप्ता,शिव जी गुप्ता,ब्यूरो चीफ विष्णू गुप्ता,पत्रकार विवेक,, गोपाल बाजपेई ,दुर्गेश गुप्ता , अतुल गुप्ता , पारुल गुप्ता , शिव जी, बिपिन बिहारी, राजा गुप्ता विवेक गुप्ता, शशांक गुप्ता सहित काफी संख्या में भक्तगण मौजूद थे।

दिगम्बर स्वामी आश्रम में परम्परागत 153वें जल विहार मेले का हुआ आयोजन

संवादाता उमेश द्विवेदी।

पुरवा,उन्नाव। श्री दिगम्बर स्वामी आश्रम में परम्परागत 153 वें जल विहार मेले का आयोजन सम्पन्न हुआ।जिसमें ग्रामीण बाल कलाकारों ने भगवान कृष्ण के जन्म से लेकर कंस वध तक की लीला का सफल व सजीव मंचन किया।मेले का बंउड़रा राक्षस दर्शकों का मुख्य आकर्षण रहा।रात्रि में भी हास्य व मनोरंजन कार्यक्रम का आयोजन किया।

वि०खं० के अन्तर्गत ग्रामसभा मिजार्पुर-सुम्हारी के श्रीश्री १००८ दिगम्बर स्वामी आश्रम में परम्परागत १53 वें जलविहार मेले का आयोजन किया गया।जिसमें स्थानीय ग्रामीण बाल-युवा व वृद्ध कलाकारों ने भगवान वासुदेव के जन्म से कंसवध तक की लीला का सफल व सजीव मंचन किया।मेले में पूतनावध, बकासुर, बृषभासुर व बौंड़रा राक्षस वध बाद बरहौं तालाब में बालकृष्ण ने कालिया नाग के मान मर्दन व कंसवध आदि के सफल मंचन की क्षेत्रीयजनों ने काफी सराहना की।

मेले में आनंद शंकर संकीर्तन मण्डल की भगवान कृष्ण की भक्ति रस से सराबोर गीतों की प्रस्तुति ने समां बाधा।साथ ही ग्रामीणों द्वारा दर्शाई गयी हास्य व ब्यंग्य रस की विभिन्न झांकियों ने समाज को भारतीय व पाश्चात्य सभ्यता को भी आईना भी दिखाया।बाल कलाकारों में से अत्युष शुक्ला-कृष्ण, अंशुमान बाजपेई-राधा, अंश बलराम-बलराम, नवीन तिवारी-हनुमान व सुनील दुबे ने महर्षि नारद व वयोवृद्ध शिवम् शुक्ला ने पूतना का सजीव मंचन कर खूब तालियां बटोरीं।

मौके पर ग्राम प्रधान संतोष पाल, राजू शुक्ला, कृपा शंकर शुक्ला, संजीव कुमार, राकेश अवस्थी, गरिमा-महिमा, सन्तो देवी, ममता देवी, विश्वंभर नाथ तिवारी, रमेशचन्द्र बाजपेई, श्याम सुन्दर, रबि शुक्ला, लिलऊ तिवारी, प्रेम सविता, सोहन, गंगा प्रसाद, शिवराम व बाबू लाल लोधी सहित हजारों क्षेत्रवासी मेले मे मौजूद थे।

सपा और बसपा की विचारधारा में जमीन आसमान का अंतर: शर्मा

मथुरा, संवाददाता।

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) अध्यक्ष मायावती और समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच मतभेदों के खुलासे पर उत्तर प्रदेश के पूर्व उपमुख्यमंत्री सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि बसपा और सपा की विचारधारा में जमीन आसमान का अन्तर है।वृन्दावन में पत्रकारों से बातचीत में डा शर्मा ने कहा कि सपा के शासनकाल में बसपा कार्यकताओं पर सबसे अधिक अत्याचार हुए। अखिलेश सरकार में दलित उत्पीड़न चरम पर था।

यही कारण था कि दोनो दलों के गठबंधन को कार्यकर्ता आसानी से पचा नहीं पा रहे थे। उन्होंने कहा जब बसपा को दस और सपा को केवल पांच सीट मिलीं तो सपा ने यह अनुभव किया कि सपा का वोट तो बसपा को मिल गया है पर बसपा का वोट सपा को नही मिला है। संभवत: उसके बाद ही दोनो नेताओं में मतभेद हो गए । वैसे भी सपा दलित विरोधी है।उन्होने कहा कि भाजपा की नजर में सब जातियां समान हैं। प्रधानमंत्री ने तो केवल चार जातियां युवा, किसान, महिला और गरीबी को ही जाति माना है तथा उनके ही कल्याण के लिए कहा है।

डा शर्मा ने विरोधी दलों को गरीबों और पिछड़ों के लिए काम करने की सलाह दी क्योंकि जातिवाद एक जहर है और देश की प्रगति में सबसे अधिक बाधक है। इतिहास साक्षी है कि लगभग ढाई सौ साल पहले जाति व्यवस्था की जगह केवल वर्ण व्यवस्था ही थी। मुगलों और अंग्रेजों ने सत्ता में बने रहने के लिए ही जाति व्यवस्था शुरू की थी। चूंकि इतिहास को अधिकतर विदेशियों ने लिखा इसलिये उन्होंने उस सनातन संस्कृति को कमजोर करने का प्रयास किया जो देश की एकता का मूल है। ार्मा ने कहा कि आज कांग्रेस वही काम कर रही है तथा देश को कमजोर करने के किसी प्रयास से पीछे नही हट रही है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी येन केन प्रकारेण सत्ता में आना चाह रहे हैं यद्यपि सत्ता उन्हें मिलने वाली नही है।

पेज 1 का शेष

पत्रकार हितों के लिए सरकार प्रतिबद्ध......

सदस्यों को बधाई दी।इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष हेमंत तिवारी और सचिव भारत सिंह ने वरिष्ठ पत्रकारों को पेंशन दिए जाने की मांग रखी।पत्रकार कल्याण कोष की माँग के तहत पत्रकारों के स्वास्थ्य कोष की माँग की गई।समिति के सचिव भारत सिंह ने कहा कि लघु व मध्यम समाचार पत्र आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं।सरकार उन्हें निमानुसार विज्ञापन जारी कर आर्थिक संकट से उबरने में मदद करें। प्रमाण पत्र वितरण समारोह में मुख्य रूप से समिति के निर्वाचित उपाध्यक्ष आकाश शेखर शर्मा,अविनाश, चंद्र मिश्रा,राघवेंद्र त्रिपाठी, कोषाध्यक्ष, आलोक कुमार त्रिपाठी संयुक्त सचिव विजय कुमार त्रिपाठी, अनिल कुमार सैनी,नीता देवी मिश्रा कार्यकारिणी सदस्य दिलीप सिन्हा,रितेश सिंह,अब्दुल वहीद,नवेद सिकोह,शेखर पंडित,वेद प्रकाश दीक्षित,भूपेंद्र मणि त्रिपाठी,राघवेंद्र प्रताप सिंह, रेनू निगम,सतेंद्र राय उपस्थित थे। इस समारोह में दो निर्वाचित सदस्य शबीबुल हसन और सुयश मिश्रा किसी कारण वश उपस्थित नहीं हो सकें। जिनका प्रमाण पत्र सचिव भारत सिंह ने हासिल किया।कार्यक्रम में चुनाव समिति के सदस्य डॉ. कलानिधि मिश्र, विजय उपाध्याय,डॉ. सुल्तान शाकिर हाशमी,डॉ. नासिर खान, नायला किदवई,आसिफ रजा जाफरी, डॉ. अशोक यादव,आलोक द्विवेदी, गंगेश और शाश्वत तिवारी भी उपस्थित थे।

5 वर्ष में खत्म होगी डॉक्टरों....

में उत्कृष्ट कार्य हेतु क्लीनिकल व पैरा क्लीनिकल फैकल्टी के सदस्यों को पुरस्कृत किया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अच्छा करने के अच्छे तथा बुरा करने के बुरे परिणाम प्राप्त होते हैं। संस्थान के निर्माण मात्र से ही समस्या का समाधान नहीं होता। यदि संस्थान अच्छे हाथों में होगा, तो फल-फूल कर व संस्कृति की तरह आगे बढ़कर अन्य लोगों के लिए प्रेरणादायी बनेगा। आपके द्वारा किये गये परिश्रम और पुरुषार्थ का लाभ जनता-जनार्दन को प्राप्त होगा। इस यश के भागीदार संस्थान के साथ-साथ विभाग एवं सरकार भी बनेंगे। संस्थान के गलत हाथों में जाने तथा उसकी दिशा गलत होने से मिलने वाले अपयश के भागीदार संस्थान के साथ-साथ विभाग एवं सरकार भी बनते हैं। किसी भी संस्थान द्वारा किए गए कार्य से आम जनमानस को पीड़ा मिलने पर, उसके द्वारा जो टिप्पणी की जाती है, वही अपयश कहलाता है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि लखनऊ में प्रदेश की लगभग 70 लाख आबादी निवास करती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमोत्तर बिहार तथा नेपाल की बड़ी आबादी अपनी स्वास्थ्य सुविधा के लिए लखनऊ पर निर्भर करती है। मरीज स्वास्थ्य सुविधा के लिए सबसे पहले डॉ0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में आते हैं। प्रदेश में लगभग 25 करोड़ आबादी निवास करती है। इतनी बड़ी आबादी को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना चुनौती के साथ-साथ अवसर भी प्रदान करता है। यह आपके लिए अनेक प्रकार के कार्यों एवं सेवाओं के साथ-साथ अनुसंधान एवं विकास का माध्यम बन सकता है। के0जी0एम0यू0, आर0एम0एल0 तथा एस0जी0पी0जी0आई0 में आने वाले मरीजों को निचले स्तर पर ही जिला अस्पताल, सी0एच0सी0 तथा पी0एच0सी0 आदि में स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाएं। प्रदेश में विगत ढाई वर्षों से टेली मेडिसिन के क्षेत्र में भी बहुत अच्छे काम किए गए हैं। प्रत्येक सप्ताह जिले स्तर की स्वास्थ्य टीम द्वारा पी0एच0सी0 में आरोग्य मेले का आयोजन किया जा रहा है। इससे करोड़ों की संख्या में लोग लाभान्वित हुए हैं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आज यहां संस्थान के निदेशक द्वारा संस्थान की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है। इसमें बताया गया कि संस्थान द्वारा यू0जी0, पी0जी0 एवं सुपर स्पेशियलिटी सहित अन्य विभागों का संचालन सफलतापूर्वक किया जा रहा है। यह संस्थान छोटे से चिकित्सालय से बढ़कर 1300-1400 बेड के एक बड़े चिकित्सालय के रूप में अपनी सुविधाएं प्रदान कर रहा है। यह ऑर्गन ट्रांसप्लांट की दिशा में भी आगे बढ़ चुका है। किसी भी संस्थान द्वारा स्थापना दिवस पर इस प्रकार की वार्षिक रिपोर्ट व प्रतिवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक है। इसके माध्यम से संस्थान द्वारा स्वयं का आकलन करने के साथ ही भविष्य की कार्य योजना भी तैयार की जा सकती है। यह आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इस संस्थान में लाखों की संख्या में मरीज अपना उपचार करा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मरीज के रोग, लक्षणों तथा उपचार आदि की कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करते हुए, तकनीक का उपयोग करते हुए डाटा रिपोर्ट संकलित करने की आवश्यकता है। प्रत्येक फैकल्टी के लिए स्टडी पेपर लिखना अनिवार्य किया जाना चाहिए। नेशनल तथा इण्टरनेशनल जर्नल्स में उनके लेख प्रकाशित किए जाने चाहिए। इन गतिविधियों पर अनुसंधान व विकास कार्य को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। तत्पश्चात पेटेंट की कार्यवाही से जुड़ना चाहिए। इसके माध्यम से संस्थान प्रगति करता हुआ दिखाई देगा तथा लोगों के विश्वास का प्रतीक बनेगा। हमें स्वयं को वर्तमान प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि डॉक्टर के बारे में कहा जाता है कि वह जितना अनुभवी होगा उसका लाभ मरीजों को उतना ही अधिक प्राप्त होगा। उन्होंने अनुभव साझा करते हुए कहा कि गोरखपुर में एक डॉक्टर ने उनके हाथ का उपचार कुछ ही समय में कर दिया था। यह डॉक्टर के अनुभव के कारण ही सम्भव हो सका। उस डॉक्टर ने पारम्परिक उपचार पर बल दिया। दवाओं को मरीज की आवश्यकता के अनुसार दिया जाना चाहिए। कोई भी दवा प्रत्येक मरीज के लिए अनुकूल नहीं होती। दवाओं के अनावश्यक प्रयोग से उनके प्रतिकूल प्रभाव की आशंका रहती है। इस बारे में मरीजों में जागरूकता प्रसारित की जानी चाहिए। उन्हें अपना खान पान तथा दिनचर्या नियमित करने की सलाह भी दी जानी चाहिए। ताकि वह अंदर तथा वाह्य दोनों रूप से स्वस्थ दिखें। नियमित दिनचर्या आरोग्यता की पहला लक्षण है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति करते हुए लोगों को फैसिलिटेट करने का काम किया गया है। प्रदेश में 05 करोड़ 11 लाख लोगों को आयुष्मान भारत के गोल्डन कार्ड प्रदान किये गये हैं। हाल ही में केन्द्र सरकार द्वारा 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्तियों को आयुष्मान भारत के अन्तर्गत 05 लाख रुपये तक की नि:शुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री राहत कोष के माध्यम से जरूरतमन्दों के गम्भीर रोगों के उपचार के लिए बिना भेदभाव धनराशि की व्यवस्था की जाती है। संस्थान के प्राध्यापकगण, रेजिडेंट डॉक्टर्स आदि का मरीजों तथा उनके अटेंडेंट के साथ व्यवहार बहुत मायने रखता है।

झांसी में पीएम सूर्यघर योजना सुस्त, रोका गया पीओ नेडा वेतन

झांसी, संवाददाता।

लोगों को मुफ्त बिजली मुहैया कराने के साथ साथ सौर ऊर्जा और सतत विकास के उद्देश्य से शुरू की गयी पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की उत्तर प्रदेश के झांसी जनपद में सुस्त रफ्तार पर प्रशासन ने कड़ा रुख अपना लिया है ।

यहां विकास भवन सभागार में शुक्रवार को जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने योजना की समीक्षा बैठक में जनपद में योजना के कार्यान्यवय में संबंधितों की लचर कार्यप्रणाली पर फटकार लगाते हुए पीओ नेडा का वेतन रोके जाने का आदेश दिया साथ ही उनसे स्पष्टीकरण भी मांगा। बैठक में जिलाधिकारी ने उपस्थितों को बताया कि यह योजना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि इस योजना का अधिक से अधिक लाभ ऐसे गरीब उपभोक्ता को प्राप्त हो जो विद्युत बिल जमा करने में असमर्थ हों एवं जो अधिक विद्युत बिल जमा कर रहे हैं।

योजना का उद्देश्य देश में घरों को मुफ़्त बिजली उपलब्ध कराना है, जिसके तहत, घरों को बिजली स्थापित करने के लिए सब्सिडी दी जाएगी वह अपनी छतों पर सोलर पैनल लगवाएं। उन्होंने योजना की अब तक की सुस्त रफ्तार पर नाराजगी

व्यक्त करते हुए उपस्थित विद्युत विभाग के मुख्य अभियंता एवं अधीक्षंण अभियंता की लचर कार्य शैली पर असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने विद्युत विभाग एवं पीओ नेडा को निर्देश दिया कि इस तरह से मिलकर काम करें कि लोगों को योजना का अधिक से अधिक लाभ दिया जा सके। लोगों से फोन से संपर्क कर आवेदन कराएं। ऐसे स्थान जहां लाइन लॉसेस अधिक है उनको भी लक्षित रखने के निर्देश दिए।

योजना का लक्ष्य जनपद सहित देश भर में एक करोड़ घरों की छतों पर सौर पैनल लगाना है, जिससे हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जा सके। इस पहल में लोगों के बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित की जाने वाली पर्याप्त सब्सिडी शामिल है और वित्तीय बोझ को कम करने के लिए भारी रियायती बैंक ऋण प्रदान किए जाते हैं।बैठक में उपस्थित वेन्डर्स ने विद्युत विभाग द्वारा सहयोग न किए जाने की शिकायत करते हुए कहा कि विभाग योजना अंतर्गत लाभार्थियों द्वारा किए गए आवेदनों को अनावश्यक रूप से लंबित रखा जाता है, जबकि समस्त प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी की जानी है। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा सब्सिडी के संबंध में कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही। वेंडर्स ने बताया कि नेट मीटर टेस्टिंग के संबंध में भी विभाग द्वारा लगातार परेशान किया जा रहा है।

बैठक में परियोजना अधिकारी वैकल्पिक ऊर्जा वीरेन्द्र जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद को 50 हजार का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसके सापेक्ष अब तक 14930 लोगों ने पंजीकरण करा लिया है। पंजीकरण कराने वालों में 2411 ने आवेदन किया जिसकी कैपेसिटी 8300.05 किलोवाट है,अब तक 783 लाभार्थियों के यहां योजना अंतर्गत सौलर पैनल लगा दिए गए हैं जिसकी कैपेसिटी 2778.87 किलो वाट है।

उन्होंने बताया कि छत पर सौलर पैनल लगाना एकदीर्घकालिक निवेश है। 01 किलोवाट से 120 यूनिट तक बिजली पैदा हो सकती है और 03 किलोवाट के सोलर पैनल से कुल सालाना बचत 07 रुपये प्रति यूनिट पर 30,240 रुपये किया जा सकता है, हालांकि 03 किलोवाट पर लागत 02 लाख रुपये होती है और सब्सिडी के रूप में 78000 रुपये दिये जाते हैं तो ऐसे में 01.20 लाख रुपये का लागत पड़ती है।

महिमा चौधरी @51

मुंबई, एजेंसी।

बॉलीवुड की जानी-मानी अभिनेत्री महिमा चौधरी आज 51 वर्ष की हो गयी।महिमा चौधरी का जन्म पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में 13 सितंबर 1973 को हुआ था। उन्होंने दसवीं कक्षा तक कुसेओंग में डॉवहिल में पढ़ाई की और बाद में दार्जिलिंग के लोरेटो कॉन्वेंट में चली गई । उन्होंने स्थानीय सौंदर्य प्रतियोगिता में 'मिस दार्जिलिंग' का खिताब जीता।महिमा ने बतौर अभिनेत्री अपने करियर की शुरूआत वर्ष 1997 में प्रदर्शित सुभाष घई की ब्लॉककबस्टर फिल्म परदेस से की।इस फिल्म के लिये उन्हें सर्वश्रेष्ठ डेब्यू अभिनेत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार दिया गया।अपनी पहली रिलीज परदेस से पहले , उन्होंने अपने निर्देशक सुभाष घई की सिफारिश पर अपना नाम बदलकर महिमा चौधरी रख लिया , जो मानते थे कि 'एम' अक्षर उनकी फिल्मों में अग्रणी अभिनेत्रियों के लिए भाग्यशाली होता है।

वर्ष 2000 में प्रदर्शित फिल्म धड़कन में अपने बेहतरीन अभिनय के लिये महिमा सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार से नामांकित की गयी।वर्ष 2006 में शादी करने के बाद महिमा चौधरी ने फिल्मों में काम करना कुछ कम कर दिया था। जब महिमा काम कर रही थीं, उसी दौरान उनका एक भयानक एक्सीडेंट भी हुआ था। फिल्म दिल क्या करे की शूटिंग के दौरान महिमा चौधरी का कार एक्सीडेंट हुआ था. उस दौरान उनके चेहरे में कांच के टुकड़े धंस गए थे. उस दौरान महिमा के चेहरे से कांच के 67 टुकड़े निकाले गए थे।वर्ष 2006 में महिमा ने बिजनेसमैन बॉबी मुखर्जी से शादी की थी , लेकिन वर्ष 2013 में दोनों का तलाक हो गया। महिमा की एक बेटी है जिसका नाम आर्यना है।महिमा की जिंदगी में सिर्फ एक्सीडेंट ही नहीं, बल्कि एक और बड़ा चैलेंज ब्रेस्ट कैंसर के रूप में आया, लेकिन महिमा ने हिम्मत नहीं हारी और इस बीमारी से भी लड़ाई जीती।महिमा ने अपनी बेटी आर्यना का जिक्र करते हुए बताया था कि जब वो कैंसर से परेशान थीं, तब उनकी बेटी ने स्कूल जाना छोड़ दिया था, जिससे उनकी मम्मी को कोविड 19 का खतरा न हो। महिमा चौधरी अब पूरी तरह ठीक हो चुकी हैं और जल्द ही फिल्म इमरजेंसी में नजर आने वाली हैं। इस फिल्म में महिमा, कंगना रनौत के साथ स्क्रीन शेयर करेंगी।महिमा ने फिल्म इमरजेंसी में पुपुल जयकर का किरदार निभाया है। पुपुल जयकर एक लेखिका थीं और श्रीमती इंदिरा गांधी की बहुत करीबी दोस्त थी। उन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी की आत्मकथा भी लिखी हैं। महिमा चौधरी ने अपने सिने करियर में लगभग 35 फिल्मों में अभिनय किया है।उनके करियर की अन्य उल्लेखनीय फिल्मों में कुछ है। दाग द फायर, कुरूक्षेत्र, दिल क्या करे, लज्जा, दीवाने, खिलाड़ी 420, ओम जय जगदीश, दिल है तुम्हारा, सौतन, सहर, सैंडविच और बागबान आदि.

खास खबर

बंगलादेश का चीन से ऋण ब्याज दर कम करने का आग्रह

ढाका। बंगलादेश सरकार ने चीन से मौजूदा ऋणों पर ब्याज दर को घटाकर एक प्रतिशत करने और भुगतान अवधि को बढ़ाकर 30 वर्ष करने का अनुरोध किया है।मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक चीनी ऋणों पर वर्तमान में ब्याज दर दो से तीन प्रतिशत के बीच है और भुगतान अवधि 20 वर्ष है। आर्थिक संबंध प्रभाग (ईआरडी) सचिव शहरियार कादर सिद्दीकी ने बताया कि ब्याज दरों को कम करने के लिए वित्त मंत्रालय के ईआरडी ने इस सप्ताह की शुरूआत में चीन को पत्र लिखा है ईआरडी अधिकारियों के अनुसार यदि वे ऐसा करने में असमर्थ हैं.

नेपाल में जापानी इंसेफलाइटिस वायरस से 12 लोगों की मौत

काठमांडू। नेपाल में जून में मानसून आने के बाद से जापानी इंसेफलाइटिस (जेई) वायरस से बच्चों सहित 12 लोगों की मौत हो गई और 59 लोग संक्रमित हुए हैं।काठमांडू पोस्ट के अनुसार, काठमांडू घाटी सहित 29 जिलों में खतरनाक वायरस से संक्रमण की सूचना मिली है, जिनमें से आठ जिलों कैलाली, कपिलवस्तु, पाल्पा, चितवन, रौतहट, सरलाही, सिराहा और सुनसारी में संक्रमण से 12 लोगों की मौतों की पुष्टि हुई है।स्वास्थ्य सेवा विभाग में परिवार कल्याण प्रभाग के निदेशक डॉ. बिबेक कुमार लाल ने कहा, जेई वायरस के फैलने के लिए सितंबर और अक्टूबर चरम महीने हैं। उन्होंने कहा, हमने पहले से ही निगरानी बढ़ा दी है और वायरस के संक्रमण प्रसार चक्र को तोड़ने के लिए तैयारी कर ली है। जापानी इंसेफलाइटिस वायरस के कारण होने वाला एक मस्तिष्क संक्रमण है, जो पूरे एशिया और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में फैला हुआ है।

ब्रिटेन की रॉयल नेवी ने रूसी जहाजों को घेरा: रक्षा मंत्रालय

लंदन। ब्रिटेन की रॉयल नेवी ने रूसी जहाजों को घेरा, जबकि रॉयल एयर फोर्स (आरएएफ) ने दो रूसी विमानों को रोका। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में यह जानकारी दी। हालांकि मॉस्को कई बार कह चुका है कि रूसी हवाई बल के विमानों की सभी उड़ानें अंतरराष्ट्रीय हवाई क्षेत्र नियमों का सख्त पालन करती हैं। मंत्रालय ने कहा कि एचएमएस आयरन ड्यूक और एचएमएस टाइन ने ब्रिटेन के जल क्षेत्र में चार रूसी जहाजों को घेरा और आरएएफ जेट विमानों ने एक रूसी बियर विमान को रोका, जो ब्रिटेन के जलक्षेत्र में आ रहा था।

डिप के साथ स्नैक्स खाने से बढ़ सकती है कैलोरी की मात्रा

नई दिल्ली (आईएएनएस)। एक शोध से यह बात सामने आई है कि नमकीन स्नैक्स के साथ डिप का इस्तेमाल न करने से कैलोरी कम करने में मदद मिल सकती है। अमेरिका में पैन स्टेट सेंसरी इवैल्यूएशन सेंटर में किए गए नवीनतम शोध में यह बात सामने आई कि जब उपभोक्ताओं को नमकीन स्नैक के साथ डिप परोसा जाता है तो जो उसका सेवन करते हैं और जो उससे बचते हैं तो उनके शरीर पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? शोध के निष्कर्षों से पता चला कि जिन लोगों ने चिप्स और डिप एक साथ खाए, उन्होंने केवल चिप्स खाने वालों की तुलना में 77 प्रतिशत अधिक कैलोरी इनटेक किया। हालांकि, फूड क्वालिटी एंड प्रेफरेंस पत्रिका में प्रकाशित शोध से पता चला है कि चिप्स का मात्रा में कोई अंतर नहीं था। खाद्य विज्ञान के प्रोफेसर और केंद्र निदेशक जॉन हेस ने कहा, जब डिप उपलब्ध थी तो लोगों ने कम चिप्स नहीं खाए, उन्होंने चिप्स के साथ डिप की मात्रा भी उतनी ही ली। इसका मतलब यह है कि चिप्स में डिप मिलाने से लोगों में कैलोरी की मात्रा में काफी वृद्धि हो सकती है और उन्हें इसका एहसास भी नहीं होता। अध्ययन में 46 वयस्क प्रतिभागियों का मूल्यांकन किया गया, जिन्हें 70 ग्राम रैंच-फ्लेवर वाले चिप्स, या लगभग 2.5 सर्विंग्स के बराबर या लगभग एक तिहाई कप रैंच डिप के साथ या बिना डिप के परोसे गए। टीम ने पाया कि लोगों ने बिना डिप के भी उतनी ही मात्रा में चिप्स खाए, जिससे डिप उपलब्ध होने पर उनकी कैलोरी की मात्रा में काफी वृद्धि हुई। औसतन लोगों ने एक बार में चिप्स और डिप इनटेक से 345 कैलोरी प्राप्त की, जबकि अकेले चिप्स सेवन से उन्हें 195 कैलोरी मिली।

चिप्स और डिप एक साथ खाए, उन्होंने केवल चिप्स खाने वालों की तुलना में 77 प्रतिशत अधिक कैलोरी इनटेक किया। हालांकि, फूड क्वालिटी एंड प्रेफरेंस पत्रिका में प्रकाशित शोध से पता चला है कि चिप्स का मात्रा में कोई अंतर नहीं था।

नासा ने किया बड़ा खुलासा: सुनीता विलियम्स को स्टारलाइनर से वापस न लाना था सही फैसला

वापसी में आई थी खराबी

वॉशिंगटन, एजेंसी।

अंतरिक्ष में फंसे बोइंग स्टारलाइनर कैप्सूल ने पिछले सप्ताह पृथ्वी पर वापसी की है। तकनीकी खराबियों के कारण इसमें देरी हुई है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अलग होने के छह घंटे बाद अंतरिक्ष यान न्यू मैक्सिको के व्हाइट सैंड्स मिसाइल रेंज में पैराशूट के जरिए उतरा। जब यह उतर रहा था तब अंधेरा था और रेगिस्तान में यह ऑटोपायलट मोड पर उतरा। जून में यह स्पेस में गया था, लेकिन थ्रस्टर में खराबी के कारण वहीं फंस गया। वापसी से पहले कई महीनों तक ड्रामा चलता रहा। बोइंग स्टारलाइनर के जरिए अंतरिक्ष यात्री बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर ले जाया गया था। यह स्टारलाइनर का पहला मानव मिशन था। हालांकि दोनों अंतरिक्ष यात्री इसके जरिए वापस नहीं लौटे हैं।

स्टारलाइनर में खराबी के कारण इसके जरिए अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी जोखिम भरी थी। नासा के वैज्ञानिकों ने इसकी जगह उन्हें स्पेसएक्स के क्रू ड्रैगन के जरिए वापस पृथ्वी पर लाने का विकल्प चुना है। इस निर्णय का मतलब है कि स्पेस स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्री फरवरी तक रहेंगे। तकनीकी खराबियों के कारण नासा के कॉमर्शियल क्रू प्रोग्राम के मैनेजर स्टीव स्टिच ने बिना चालक दल के कैप्सूल के वापसी की प्रशंसा की। इसके साथ ही वापसी को बुल्सआई लैंडिंग बताया। मतलब यह एकदम निशाने पर उतरा। क्रर और नासा के विमानों पर लगे कैमरों ने स्टारलाइनर को उतरने में मदद की। नासा ने फैसला लिया है कि वह स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन से दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाएगा। सुनीता विलियम्स ओर विल्मोर आज पृथ्वी के साथ जुड़कर स्पेस से बातचीत करेंगे। नासा के प्रशासक बिल नेल्स ने अगस्त में कहा था कि अंतरिक्ष की उड़ान जोखिम भरी होती है। भले ही यह सबसे सुरक्षित ही क्यों न हो। उन्होंने कहा, 'एक टेस्ट फ्लाइट न तो सुरक्षित है और न ही रेगुलर चलने वाली उड़ान है। बुच और विलियम्स दोनों को स्पेस स्टेशन पर रखने और बिना चालक दल के स्टारलाइनर को वापस लाना सुरक्षा को लेकर हमारी प्रतिबद्धता का परिणाम है।

वापसी के दौरान आई खराबी

स्टारलाइनर की वापसी के दौरान एक और थ्रस्टर में खराबी आई। वहीं पूरा सिस्टम कुछ समय के लिए बंद हो गया था। ऐसे में यह किस्मत की बात है कि स्टारलाइनर सुरक्षित आ गया। स्टिच ने कहा, 'मुझे लगता है कि हमने दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को वापस न लाने का सही फैसला लिया था। हम सभी सफल लैंडिंग से खुश हैं। फिर भी हमारे मन में एक ही भावना है कि हम जैसा चाहते यह वैसा नहीं हुआ।' कैप्सूल की वापसी बोइंग की ओर से व्यापक परीक्षण के बाद हुई। तब कहा गया था कि स्टारलाइनर अंतरिक्ष यात्रियों को लाने के लिए सुरक्षित है।

बुकिंग.कॉम ने यात्रा को बनाया आसान: सोनाक्षी

मुंबई, एजेंसी।

बॉलीवुड की दबंग गर्ल सोनाक्षी सिन्हा का कहना है कि बुकिंग.कॉम ने यात्रा को बहुत आसान बना दिया है।बुकिंग.कॉम जो दुनिया की प्रमुख ऑनलाइन ट्रैवल कंपनियों में से एक है।यात्रियों के लिए बेहतरीन सुविधाएं प्रदान कर रही है। कंपनी का उद्देश्य है कि हर यात्रा को एक 'कनेक्टेड ट्रिप' में बदल दिया जाए, जहां सब कुछ एक ही जगह से आसानी से प्लान हो सके।बॉलीवुड की मशहूर जोड़ी सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल ने बुकिंग.कॉम के भारत, श्रीलंका, मालदीव और इंडोनेशिया के कंट्री मैनेजर संतोष कुमार के साथ मिलकर एक गाइडेड कुकिंग सेशन का मजा लिया।इस आयोजन में बुकिंग.कॉम पर उपलब्ध कई रोमांचक अनुभवों और आकर्षणों में से एक पर खास ध्यान दिया गया।

सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल ने अपने पकवानों से प्रेरित यात्रा की कहानियां साझा कीं। उन्होंने यहां अपने पसंदीदा एवोकैडो और खीरे की सुशी के साथ सत्तू के पराठे, बैंगन और टमाटर की चटनी बनाना सीखा, जो बिहार का एक खास व्यंजन है।सोनाक्षी सिन्हा ने कहा, यात्रा करना मेरा जुनून है। मुझे जहां भी जाना हो, वहां की संस्कृति में घुलना-मिलना, लोकल बाजारों में खरीदारी करना और स्थानीय खाने का आनंद लेना बहुत पसंद है।

लेकिन यात्रा की प्लानिंग करना कभी-कभी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फ्लाइट, होटल और बाकी गतिविधियों को संभालना थका देने वाला काम हो सकता है।

शुक्र है कि बुकिंग.कॉम ने इसे आसान बना दिया है। अब यात्री एक ही प्लेटफॉर्म से अपनी यात्रा की सारी चीजें बुक कर सकते हैं और बिना किसी तनाव के छुट्टियों का मजा ले सकते हैं।

पेज 1 का शेष

अबकी बार 10....

के पीछे की वजह यह बताई जा रही है कि इन दोनों सीटों पर चुनावी प्रबंधन की कमान स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाली है, इसलिए दावेदार अपनी जीत सुनिश्चित मान रहे हैं। जिस तरह से सीएम ने दोनों सीटों पर फोकस किया है उससे यहां माहौल काफी बदला है। इससे भाजपा व सहयोगी दलों के दावेदारों की उम्मीदे बढ़ और गई हैं। सूत्रों की माने तो मिल्कीपुर में एक पूर्व सांसद अपने एक करीबी को चुनाव लड़ाना चाहते हैं तो कटेहरी सीट के प्रभारी बनाए गए एक मंत्री भी अपने चहेते को टिकट दिलाने के लिए पूरी ताकत लगाए हैं। संगठन के कई पदाधिकारी भी टिकट की लाइन में हैं। कटेहरी में निषाद पार्टी की दावेदारी के अलावा भाजपा की ओर से भी आधे दर्जन नेताओं में भी टिकट की होड़ है।

राजस्व विभाग में खाली पदों को भरेगी.....

का नवीन पद सृजित करने की भी जरूरत बताई। शुक्रवार को एक उच्चस्तरीय बैठक में राजस्व विभाग के कामकाज और उपलब्ध मानव संसाधन की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व विभाग और राजस्व परिषद में काम के बदलते स्वरूप और अधिकता को देखते हुए दक्ष युवाओं की तैनाती की जानी चाहिए। नवीनतम तकनीकों को अपनाने के लिए तहसील, जिला, मंडल और राजस्व परिषद में आई.टी. में दक्ष लोगों की तैनाती की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आम जनता के कार्यों में राजस्व विभाग के कार्मिकों को प्रायः फील्ड विजिट करना पड़ता है। ऐसे में यह उचित होगा कि लेखपालों और राजस्व निरीक्षकों को वाहन भत्ता दिया जाना चाहिए। इसी तरह नायब तहसीलदार की कार्यक्षमता में बढ़ोतरी के लिए उन्हें चार पहिया वाहन की उपलब्धता कराई जाए। साथ ही, जीपीएस से संबंधित कार्यों के बेहतर संपादन के लिए लेखपालों और राजस्व निरीक्षकों को नए टैबलेट भी उपलब्ध कराए जाएं।उन्होने निर्देश दिए कि आम जन से जुड़े कार्यों को समयबद्धता के साथ मेरिट के आधार पर निस्तारित किया जाए, अनावश्यक कहीं भी कोई प्रकरण लंबित न रहे। राजस्व कार्मिकों के प्रशिक्षण पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने राजा टोडरमल सर्वेक्षण भूलेख प्रशिक्षण संस्थान, हरदोई में आधारभूत अवसंरचना को और बेहतर करने के निर्देश भी दिए।मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद विभाग स्तर पर प्रस्ताव तैयार कर अग्रेतर कार्यवाही की जाएगी। बैठक में मुख्य सचिव, अध्यक्ष राजस्व परिषद, प्रमुख सचिव राजस्व सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति रही।

अखिलेश हैं गठबंधन टूटने....

प्रति ईमानदार भी जरूर रहती है। सपा के साथ सन 1993 व 2019 में हुए गठबंधन को निभाने का भरपूर प्रयास किया गया, किन्तु बहुजन समाज का हित व आत्म-सम्मान सर्वोपरि।बसपा अध्यक्ष ने कहा बीएसपी जातिवादी संकीर्ण राजनीति के विरुद्ध है। अतः चुनावी स्वार्थ के लिए आपाधापी में गठबंधन करने से अलग हटकर बहुजन समाज में आपसी भाईचारा बनाकर राजनीतिक शक्ति बनाने का मूवमेन्ट है ताकि बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर का मिशन सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त कर आत्मनिर्भर हो सके।इस बारे में बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा मैं सभी को यह अवगत कराना चाहता हूं कि 2019 के लोकसभा आम चुनाव में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन टूटने की वजह सपा मुखिया खुद हैं जो आदरणीय बहन कुमारी जी ने अपनी पार्टी द्वारा जारी की गई पुस्तक में लिखा हैं।उन्होने कहा बहन जी फोन करने के पूर्व मेरे द्वारा फोन करने पर सपा प्रमुख फोन पर नही आए, फिर पार्टी कार्यालय से फोन गया और तब फिर भी फोन पर सपा प्रमुख से बात नहीं करायी गयी।फिर भी आदरणीय बहन जी ने बड़े होने के नाते सपा प्रमुख को फोन कर के हौसला देने की कोशिश की थी लेकिन वह फोन पर नहीं आए। और इस सबका परिणाम यह रहा कि बीएसपी को गठबंधन तोड़ना पड़ा।सपा प्रमुख का यह व्यवहार समाज के दलितों, वंचितों एवं शोषितों के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाला था। बीएसपी सिर्फ वोट ट्रांसफर करवाने के लिए नहीं है।

बेल वाला....

अरविंद केजरीवाल इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा की जीरो टॉलरेंस है। भ्रष्ट अरविंद केजरीवाल एक दिन झुकेंगे और लोग उनसे इस्तीफा लेंगे। दिल्ली भाजपा प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल से पद छोड़ने का आग्रह करते हुए कहा कि हम आग्रह करते हैं कि यदि उनमें कोई नैतिकता बची है, तो उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल और आप के पास कोई नैतिक चरित्र नहीं है। वे बहुत दूर हैं। सचदेवा ने आगे कहा कि आज अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी गई है। मैं कहना चाहूंगा कि आप जमानती क्लब' बन गई है और वहां अरविंद केजरीवाल का स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत गंभीर टिप्पणी की है, उसने कहा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कानूनी थी। सचदेवा ने कहा है की केजरीवाल को सशर्त जमानत मिलना कोई विशेष उपलब्धि नही है, मुकदमा चलेगा और उन्हे शीघ्र लम्बी सजा होगी। केजरीवाल याद रखें वह अब लालू यादव, मधु कोड़ा जैसे मुख्यमंत्रियों की सूची में जुड़ गये हैं और उन्हे भी जमानत मिली थी और वह शीघ्र सजा पा कर फिर जेल जायेंगे। जिन शर्तों पर अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है उनके चलते -- केजरीवाल को जमानत बेशक मिली हो पर उन्हे अब मुख्य मंत्री पद पर बने रहने का कोई अधिकार नही है। जब वह मुख्य मंत्री का काम नही कर सकेंगे तो वो मुख्य मंत्री क्यों -- अगर वो सच्चे हैं तो यह शर्त क्यों -- इस्तीफा दें ?

बदलेगी बिलासपुर स्टेशन....

के लिए तथा एक स्टेशन से निकास के लिए होगा। इसके अलावा 6051 वर्ग मीटर का कॉनकोर्स का प्रावधान किया गया है, जिसमें 1700 वर्ग मीटर का कमर्शियल एरिया होगा, जिसमें व्यवसायिक प्रतिष्ठान एवं दुकानें होगी। बुजुर्गों तथा दिव्यांग यात्रियों की विशेष सुविधा के लिए 30 लिफ्ट एवं 22 एस्केलेटर बनाए जाएंगे जिससे यात्रियों को एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म जाने में आसानी होगी । पार्सल सर्विस मूवमेंट को यात्री आवागमन एरिया से अलग रखा जाएगा जिससे यात्रियों को असुविधा न हो ।पर्यावरण संरक्षण के लिए क्लीन एनर्जी के महत्व को रेखांकित करते हुए स्टेशन की छतों पर 20500 वर्ग मीटर में 1200 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया जाएगा । जल संरक्षण के दृष्टिगत स्टेशन भवन के 16 पिट्स में 97 हजार लीटर क्षमता के रेन वाटर हार्वेस्टिंग और इमरजेंसी पावर बेक-अप के साथ फायर फाइटिंग स्थापित किए जाएंगे ।

केजरीवाल को मिली.....

करने का आदेश दिया।सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर हालांकि, दोनों न्यायाधीशों ने अलग-अलग फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति कांत ने सीबीआई की ओर से की गई श्री केजरीवाल की गिरफ्तारी को न्यायोचित करार दिया, जबकि न्यायमूर्ति भुइयां ने गिरफ्तारी को गैर जरूरी बताया। न्यायमूर्ति भुइयां ने याचिकाकर्ता की इस दलील को स्वीकार किया कि धन शोधन मामले में उनकी जमानत को विफल करने के लिए सीबीआई ने एक प्रकार से 'पहले से तय' गिरफ्तारी की थी।श्री केजरीवाल ने दिल्ली आबकारी नीति कथित घोटाले से संबंधित सीबीआई के मुकदमे में जमानत की मांग और इसी मामले में गिरफ्तारी को अलग-अलग याचिकाओं के जरिये शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी। उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय की ओर अपनी याचिकाएं ठुकराए जाने के बाद शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था।शीर्ष अदालत ने उनकी याचिकाओं पर पांच सितंबर को सुनवाई पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

उच्चतम न्यायालय की दो सदस्यीय पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता आम आदमी पार्टी के प्रमुख की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और सीबीआई की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू की घंटों दलीलें पेश की थीं।श्री केजरीवाल ने सीबीआई मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय की ओर से पांच अगस्त को अपनी याचिकाएं ठुकरा दिए जाने के बाद शीर्ष अदालत में राहत की उम्मीद में अपील दायर की थी।दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 (जो विवाद के बाद रद्द कर दी गई) के कथित अनियमितताओं के मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21 मार्च और सीबीआई ने 26 जून 2024 को आरोपी मुख्यमंत्री केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। सीबीआई की गिरफ्तारी के समय वह ईडी के मुकदमे में न्यायिक हिरासत में थे।सीबीआई ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मुकदमे में मार्च से न्यायिक हिरासत में बंद आरोपी मुख्यमंत्री से विशेष अदालत की अनुमति के बाद 25 जून को पूछताछ की थी और फिर 26 जून को उन्हें गिरफ्तार किया था।शीर्ष अदालत ने आबकारी नीति कथित घोटाले से संबंधित धन शोधन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दर्ज मुकदमे में श्री केजरीवाल को 12 जुलाई को अंतरिम जमानत दे दी थी। यदि सीबीआई की ओर जून में मुकदमा मुकदमा दर्ज नहीं किया गया होता तो वह उसी समय जेल से रिहा कर दिए गए होते।शीर्ष अदालत ने इससे पहले लोकसभा चुनाव के दौरान भी श्री केजरीवाल को 21 दिन के लिए अंतरिम जमानत दी थी। जेल से निकलने के बाद उन्होंने कई चुनावी सभाओं में भाग लिया था। सीबीआई ने आबकारी नीति बनाने और उसके कार्यान्वयन में की गई कथित अनियमितताओं के आरोप के आधार पर 17 अगस्त 2022 को एक आपराधिक मुकदमा दर्ज किया था। इसी आधार पर ईडी ने 22 अगस्त 2022 को धनशोधन का मामला दर्ज किया था। शुरू में श्री केजरीवाल का नाम आरोपियों में नहीं था।सीबीआई मामले में शीर्ष अदालत के समक्ष सुनवाई के दौरान केंद्रीय जांच एजेंसी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने मुख्यमंत्री को जमानत दिए जाने की दलीलों का पुरजोर विरोध करते हुए कहा था कि अधीनस्थ अदालत को दरकिनार करने की अनुमति केवल असाधारण परिस्थितियों में ही दी जा सकती है।

हिन्दी दैनिक सत्ता संकेत R.N.I. No.: UPHIN/2016/69492

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक एंव सम्पादक जूही सिन्हा द्वारा रूद्राक्ष प्रिन्टर्स, 89/211, राम गोपाल विद्यान्त रोड, मकबूलगंज लखनऊ (उ.प्र.) से मुद्रित कराकर एंव म.न.- 592/823, बंगाली टोला, खरिका, तेलीबाग, लखनऊ (उ.प्र.)-226029 से प्रकाशित। मो0- 9198670986, ई मेल- sattasanket@gmail.com

समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ न्यायालय होगा।